नई दिल्ली
शुक्रवार
20 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 77
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



बिहार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाकर...पेज-05

DELHIN/2014/58158

दिल्ली के स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थानों में 'एहसास'...पेज-02

एक नजर

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण: नगर निकायों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नगर निकायों को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है बल्कि हर दिन जमीन पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन दिखाई देना चाहिए। इसके लिए दैनिक निगरानी, वार्ड स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को तुर्किये के अंताल्या से वर्चुअल माध्यम से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें दिल्ली-एनसीआर के शहरों की शीतकालीन कार्ययोजनाओं और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा, सीपीसीबी की अध्यक्ष डॉ. अमनदीप गर्ग सहित विभिन्न नगर निगमों के महापौर, आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने नगर निगमों को खुले में नगर निगम का कचरा, सूखी पत्तियां और बायोमास जलाने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित करने को कहा, ताकि शिकायत मिलने के कुछ घंटों के भीतर कार्रवाई हो सके। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का पूरी तरह निस्तारण सुनिश्चित करने और पुराने कचरे के पहाड़ों को हटाने का काम समयबद्ध तरीके से तेज करने को कहा। विशेष रूप से भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट पर पुराने कचरे के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। महापौरों को नियमित रूप से वार्ड स्तर पर समीक्षा बैठकें करने और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के साथ समर्पित व्हाट्सऐप समूह बनाने को भी कहा।

भारत-जापान टू प्लस टू: मनमाने निर्यात प्रतिबंधों पर चिंता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर तथा जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजीरो ने गुरुवार को टोक्यो में चौथी भारत-जापान टू प्लस टू विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक में मंत्रियों ने मनमाने निर्यात प्रतिबंधों सहित आर्थिक दबाव और गैर-बाजार नीतियों एवं प्रथाओं के बारे में अपनी गंभीर चिंताओं को दोहराया। इनके कारण महत्वपूर्ण उद्योगों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं। मंत्रियों ने एक स्वतंत्र, खुले और कानून के शासन पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। साथ ही बल प्रयोग या धमकी का सहारा लिए बिना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि मंत्रियों ने क्वाड पहलों को पूरक और सुदृढ़ बनाने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारों को ठोस लाभ पहुंचाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग का लाभ उठाने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। मंत्रियों ने भारत में फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया।

भारत की विकास गाथा नए अवसरों का सृजन कर रही है: प्रधानमंत्री

मोदी ने फिक्की की वार्षिक आम बैठक एवं वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक एवं वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। फिक्की के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इससे पहले भी कई अवसरों पर फिक्की के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, लेकिन आज का अवसर विशेष है, क्योंकि यह संस्था बदलते समय के साथ स्वयं को आगे बढाते हुए, लगातार सजग एवं सक्रिय रहकर और भारत की आर्थिक विकास यात्रा में अपना योगदान देते हुए 100 वर्ष पूरे कर रही है।



पिछली एक शताब्दी के दौरान भारत की आर्थिक विकास यात्रा के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि पिछले 12 वर्षों में देश के नागरिकों, युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत के अथक परिश्रम ने इस प्रवृत्ति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, 'आज भारत में विकास की गति भी सबसे तेज है और गरीबी से बाहर निकलने की रफ्तार भी अभूतपूर्व है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी को मात देने में सफल रहे हैं। उन्होंने इस उपलब्धि से देश को मिलने वाले गौरव का जिक्र करते हुए कहा, 'यह रिपोर्ट हम सभी को गर्व से भर देगी।' पिछले 12 से 13 वर्षों में सही नीतियों और नेक इरादों के परिणामस्वरूप 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने पर प्रस?नता व?यक?त करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की वर्तमान विकास यात्रा से अवगत कराया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा, 'यह दर्शाता है कि आज भारत जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वह सही और सटीक है तथा इसमें देश की सफलता की गारंटी निहित है। प्रमुख वैश्विक संस्थानों द्वारा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए लगभग 7 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान व्यक्त किए जाने तथा अक्टूबर माह में लगभग 50 अरब डॉलर के रिकॉर्ड मासिक वस्तु निर्यात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इस प्रदर्शन के कारण वैश्विक एजेंसियां देश की विकास दर के अनुमानों में लगातार वृद्धि कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा, 'मूडीज रेटिंग्स, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक हमारे विकास अनुमानों में वृद्धि कर रहे हैं।'

प्राचीन शास्त्रों के श्लोक 'उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत' को उद्धृत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तियों, उद्योगों और राष्ट्रों को केवल स्थापित क्षेत्रों एवं अल्पकालिक लाभों पर निर्भर रहने के बजाय समय-समय पर आत्मचिंतन करते हुए स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर संसाधनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की स्थिति का जिक्र करते हुए फिक्की से अपनी एक शताब्दी की उपलब्धियों से आगे बढ़कर अगले 20 वर्षों की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, ताकि भारतीय उद्योग आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ व्यावसायिक विकास के नए अवसरों का लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जोर देते हुए कहा, 'अगले 20 वर्षों के लिए अपने प्रत्येक दीर्घकालिक निवेश के निर्णय का आधार 'इंडिया फर्स्ट' को बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विश्वभर में 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में जाना जाता है और तैयार दवाओं के निर्माण में देश की मजबूत स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भारत सैकड़ों श्रेणियों में अरबों डॉलर मूल्य के परि?कृत औषधीय घटकों (एपीआई), थोक दवाओं और औषधीय मध्यवर्ती उत्पादों का आयात करता है। उन्होंने फार्मास्युटिकल क्षेत्र से घरेलू विनिर्माण की संभावनाओं की पहचान करने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नई तकनीक और बड़े उत्पादन संयंत्रों में निवेश करने का आग्रह किया।

राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम कर रहे: रिजिजू

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयानों को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर राहुल गांधी के बयानों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब देश का नेता प्रतिपक्ष विदेश जाकर भारत के बारे में तथ्यहीन और गलत बातें करता है, तो आपत्ति दर्ज कराना जरूरी हो जाता है। राहुल गांधी अमेरिका और दूसरे देशों में जाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने की बात करते हैं, जबकि पूरी दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार कर रही है।



रिजिजू ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी भारत की आर्थिक प्रगति को स्वीकार कर रही हैं। इन संस्थाओं का कहना है कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ऐसे में राहुल गांधी का भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए और देश की उपलब्धियों को कमतर दिखाने से बचना चाहिए। राहुल गांधी के भारत में लोकतंत्र और वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए रिजिजू ने कहा कि यदि देश में लोकतंत्र नहीं होता तो राहुल गांधी पूरे दिन विरोध प्रदर्शन कैसे कर पाते और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा तथा सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कैसे कर पाते? उन्होंने कहा कि अगर भारत में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती तो राहुल गांधी को सुबह से रात तक अपनी बात रखने की स्वतंत्रता कहां से मिलती? केंद्रीयमंत्री ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, जहां आम नागरिक से लेकर राजनीतिक नेताओं तक सभी को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। इसके बावजूद राहुल गांधी विदेश जाकर भारत में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी इस तरह के बयानों से क्या साबित करना चाहते हैं? रिजिजू ने गरीबी के मुद्दे पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में 50 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे और अत्यधिक गरीबी से बाहर आए। उनके अनुसार, भारत ने गरीबी कम करने के मामले में दुनिया में सबसे तेज प्रगति का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने कई बार 'गरीबी हटाओ' का नारा देकर चुनाव लड़ा और सत्ता हासिल की, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में वास्तव में गरीबी खत्म करने के लिए क्या किया गया? रिजिजू ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उस स्थिति में पहुंचा है, जहां गरीबी लगभग समाप्त होने की दिशा में है और देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।

आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है इसलिए वे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी की वजह बताने को लेकर गलत तथ्य दर्ज किया और अंतरिम जमानत दी, जबकि आजम खान को गिरफ्तारी की वजह बताई गई थी।



इस संबंध में वीडियो है और पंचनामा किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए ईडी ने 18 नवंबर को ही उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 18 नवंबर को जब ईडी ने इसे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया था तो न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर तत्काल रोक लगाने और आजम खान की रिहाई रोकने की ईडी की मांग स्वीकार नहीं की। ईडी की ओर से आग्रह किया गया था कि मामले की तत्काल सुनवाई की जाए और आजम खान की जेल से रिहाई रोकने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए। इस पर न्यायालय ने कहा था कि आसमान नहीं गिर पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें। ईडी का दावा है कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित आधार उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी लेकिन उन्होंने कथित तौर पर दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था।

एजेंसी ने इस संबंध में पंचनामा और अन्य रिकॉर्ड का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर सवाल उठाया था। आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से बाहर आते ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है। 17 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी।

अमित शाह ने 'सीमा पार आतंकवाद' पर छठे वार्षिक आतंकवाद रोधी सम्मेलन का किया उद्घाटन

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में 'सीमा पार आतंकवाद' विषय पर छठे वार्षिक आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की ओर से आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्र की सामूहिक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत आयोजित किया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन के सत्र विभिन्न विषयों पर केंद्रित होंगे। इसमें विदेशी न्यायाधिकारों से साक्ष्य प्राप्त करना, आतंकवादी मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल और मुकदमों का प्रभावी प्रबंधन शामिल हैं।



सम्मेलन के सत्रों में कट्टरता का मुकाबला करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने आ रहे हाइब्रिड खतरों पर भी चर्चा होगी। अन्य सत्रों में आतंकवादी फंडिंग के नेटवर्कों को रोकने से जुड़े साधनों, तकनीकों और केस के अनुभवों की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य के लिए तैयार आतंकवाद-निरोधक रणनीतियों के विकास एवं उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर विचार किया जाएगा। इस वर्ष होने वाले सम्मेलन में राज्य पुलिस कर्मियों और पेशेवर लोगों के लिए एक क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को कई क्षेत्रों में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। इनमें आतंकवादी मामलों की जाँच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्य का उपयोग और ट्रायल रणनीति एवं प्रबंधन शामिल हैं। कार्यक्रम में आतंकी मामलों की जाँच से संबंधित विशेष प्रावधानों, बचाव पक्ष की ओर से पेश की जाने वाली सामान्य चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा तथा अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर भी चर्चा की जाएगी। दो दिवसीय विचार-विमर्श में कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ अपने अनुभव साझा कर सकेंगी, आतंकवादी मामलों से निपटने में अपनाए गए अच्छे उपायों को सामने ला सकेंगी तथा आतंकवादी मामलों की जांच से मिले सबक का लाभ उठा सकेंगी। सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों एवं विभागों के अधिकारियों तथा कानून, फॉरेंसिक एवं प्रौद्योगिकी सहित संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सहभागिता होगी।

डॉलर की तुलना में मजबूत हुआ रुपया, 7 महीने के ऊपरी के ऊपरी स्तर तक पहुंचने में सफल रही भारतीय मुद्रा

नई दिल्ली,एजेंसी। घरेलू विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार (फॉरेक्स मार्केट) में आज भारतीय मुद्रा रुपये ने अपनी बढ़त को जारी रखते हुए 7 महीने के नए ऊपरी स्तर को छू लिया। दिनभर के कारोबार के बाद भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले बंद भाव 93.45 के मुकाबले 0.16 रुपये यानी 0.17 प्रतिशत की मजबूती के साथ 93.29 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।



घरेलू शेयर बाजार में आई लगभग एक हजार अंकों की जोरदार तेजी, विदेशी संस्थागत निवेशकों की ताबड़तोड़ लिवाली और उनकी ओर से हो रहा कैपिटल इनफ्लो (पूंजी आवक) तथा डॉलर इंडेक्स में आई नरमी ने आज भारतीय करेंसी को जबरदस्त सहारा दिया। आज सुबह इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय रुपया 2 पैसे की मजबूती के साथ 93.43 प्रति डॉलर के स्तर पर खुला था। शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर की मांग बढ़ने से यह एक समय फिसल कर 93.52 प्रति डॉलर के निचले स्तर तक भी गया था। लेकिन दोपहर के सत्र में जैसे जैसे घरेलू शेयर बाजार में जोरदार लिवाली तेज होती गई और निर्यातकों की ओर से डॉलर का इनफ्लो बढ़ना शुरू हुआ, वैसे-वैसे रुपया लगातार मजबूत होता चला गया। इंट्रा-डे कारोबार के दौरान भारतीय करेंसी ने 93.1550 प्रति डॉलर के ऊपरी स्तर तक मजबूती दिखाई और अंत में 93.29 के स्तर पर बंद होने में सफल रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आई इस शानदार तेजी के साथ-साथ दुनिया की सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले भी आज भारतीय रुपये ने अपनी बढ़त कायम रखी। ब्रिटिश पॉन्ड के खिलाफ भारतीय रुपये में आज जोरदार मजबूती देखी गई, जिससे पॉन्ड पिछले बंद भाव 123.0811 के मुकाबले 0.4464 रुपये यानी 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 122.6347 के स्तर पर बंद हुआ।

चक्रवात 'अकवान' के आज आंध्र-ओडिशा तट से टकराने के आसार

नई दिल्ली,एजेंसी। पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' तेजी से तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इसके 20 नवंबर की दोपहर तक नरसपुर और पुरी के बीच गोपालपुर के निकट उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम तथा दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है। जमीन से टकराने के दौरान 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। इसके मद्देनजर उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटों के लिए 'रेड मैसेज' (चक्रवात चेतावनी) जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 20 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने तथा 21-22 नवंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अगले तीन दिनों तक सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है।



दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात 'अकवान' पिछले छह घंटों के दौरान 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ा है। आज सुबह 11:30 बजे (आईएसटी) यह पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में 15.4 डिग्री उत्तर अक्षांश और 85.2 डिग्री पूर्व देशांतर के पास केंद्रित था। यह आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से लगभग 350 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, नरसपुर से 390 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, ओडिशा के गोपालपुर से 430 किमी दक्षिण, पुरी से 490 किमी दक्षिण और चेन्नई से 600 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व में स्थित है। चक्रवात के प्रभाव से 20 नवंबर को ओडिशा के कई हिस्सों में भारी तथा कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश (21 सेमी या उससे अधिक) होने की संभावना है। इसके अलावा 20-21 नवंबर के बीच गांगेय पश्चिम बंगाल, दक्षिणी झारखंड, उत्तरी व मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण-पूर्वी बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों (असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा) में भी भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा के जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, क्योंझरगढ़ और जाजपुर जिलों तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, उत्तर-दक्षिण 24 परगना और नदिया जिलों में अचानक बाढ़ का मध्यम जोखिम जताया गया है। चक्रवात के टकराने के दौरान समुद्र में सामान्य ज्वार-भाटा के स्तर से 0.5 से 1.0 मीटर ऊंची तूफानी लहरें उठ सकती हैं। इससे आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी, कोनासीमा, काकीनाडा, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम तथा ओडिशा के गंजम और पुरी जिलों के निचले तटीय इलाकों में पानी भरने की आशंका है। समुद्र में 9-14 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठने की संभावना के मद्देनजर मछुआरों को 21 नवंबर की सुबह तक पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है।

दिल्ली के स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थानों में 'एहसास' नीति का शुभारंभ

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए 'एहसास 2026' नाम की 'मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग पॉलिसी' लॉन्च की। इस नीति का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना, विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस विषय पर खुलकर संवाद करने तथा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक एवं आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर सहित हजारों लोग उपस्थित रहे।



उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक खुशहाली को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाना आज की जरूरत है। युवाओं में बढ़ते तनाव के बीच दिल्ली सरकार की यह पहल समयानुकूल और सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे की भावनाएं, आकांक्षाएं और जरूरतें महत्वपूर्ण हैं तथा उसकी पृष्ठभूमि, क्षमता या परिस्थितियों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिव्यांग और वंचित समुदायों के बच्चों को समान अवसर, स्वीकार्यता और सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की भी है। बच्चों की भावनाओं को समझना, संवेदनशीलता से सुनना और जरूरत पड़ने पर सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि करुणा, परस्पर सम्मान और अपनेपन से बच्चों में आत्मविश्वास और मानसिक खुशहाली विकसित होती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए 'एहसास' नाम से मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग पॉलिसी लेकर आई है। यह नीति दिल्ली के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के जीवन के विभिन्न पड़ावों और मानसिक अवस्थाओं में उन्हें निरंतर सहयोग एवं संबल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'एहसास' के माध्यम से दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को मानसिक और भावनात्मक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

दिल्ली सरकार का प्रयास है कि राज्य का प्रत्येक बच्चा खुशी, सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़े तथा उसकी हर चुनौती में सरकार, शिक्षक और अभिभावक उसके साथ खड़े रहें। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की सराहना करते हुए सभी अधिकारियों, शिक्षकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के इस प्रयास में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 'एहसास 2026' नीति बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को समझने, उनकी बात सुनने और उचित सहयोग देने की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने नीति निर्माण में गुरुदेव श्रीश्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, यूनेस्को, इहबास और विशेषज्ञ संस्थाओं का आभार जताया। नीति के तहत शिक्षकों, अभिभावकों, प्रिंसिपल, ईवीजीसी, अधिकारियों, ड्राइवरों, आया और अन्य सहयोगी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि बच्चों के व्यवहार में बदलाव समय रहते पहचानकर उन्हें संवेदनशील सहयोग मिल सके।

श्रीश्री रविशंकर ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक मजबूती की आधार रही है। उन्होंने 'एहसास' नीति के लिए दिल्ली सरकार को बधाई देते हुए कहा कि यह विद्यार्थियों और समाज के बीच मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण संवाद स्थापित करेगी। दिल्ली सरकार की 'एहसास' नीति के तहत शिक्षण संस्थानों को केवल किताबी ज्ञान, परीक्षा और अंकों तक सीमित न रखकर सुरक्षित, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण वातावरण के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां विद्यार्थी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें, चुनौतियों से निपटना सीखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। 'एहसास' नीति चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला, होल-इंस्टीट्यूशन अप्रोच के तहत मानसिक स्वास्थ्य को पूरे संस्थान की कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाते हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों, फैकल्टी, संस्थान प्रमुख, हॉस्टल स्टाफ और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

वित्त का अर्थ केवल धन प्रबंधन नहीं, नैतिक अर्जन और समाज कल्याण भी है : विजेंद्र गुप्ता

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वित्त का अर्थ केवल धन का प्रबंधन करना नहीं है, बल्कि इसमें नैतिक तरीके से धन अर्जित करना, संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना और समाज के लिए समृद्धि का निर्माण करना भी शामिल है। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा वित्तीय अनुशासन, सोच-समझकर निर्णय लेने और सामूहिक कल्याण के ऐसे सिद्धांत प्रदान करती है, जो आज के आधुनिक समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यह बात विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (सांध्य) में 'भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यक्तिगत एवं कॉर्पोरेट वित्त' विषय पर आयोजित विशेष व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही।

कॉलेज के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष व्याख्यान में भारत की पारंपरिक ज्ञान परंपरा के महत्व और वर्तमान समय में व्यक्तिगत एवं कॉर्पोरेट वित्तीय गतिविधियों में उसकी उपयोगिता पर चर्चा की गई। इस पहल की सराहना करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस तरह के शैक्षणिक कार्यक्रम भारत की बौद्धिक विरासत को समझने और वर्तमान आर्थिक एवं संस्थागत व्यवस्थाओं में उसके व्यावहारिक उपयोग पर विचार करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में अर्थव्यवस्था, नैतिकता, शासन व्यवस्था और संसाधनों के जिम्मेदारीपूर्ण प्रबंधन सहित अनेक विषयों से जुड़ा ज्ञान समाहित है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिंतन में भौतिक समृद्धि के साथ नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। इन सिद्धांतों को आज की वित्तीय समझ से जोड़ने पर धन अर्जित करने और आर्थिक विकास के लिए अधिक संतुलित, नैतिक और टिकाऊ दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। विजेंद्र गुप्ता ने शिक्षा को भारत की अपनी पारंपरिक ज्ञान परंपराओं से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश की समृद्ध ज्ञान विरासत को समझने के साथ-साथ वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल एवं जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे शोध, विचार-विमर्श और विभिन्न विषयों के बीच आपसी अध्ययन को बढ़ावा दें, ताकि भारत की पारंपरिक ज्ञान परंपरा को आज की शिक्षा और अकादमिक चर्चा का हिस्सा बनाया जा सके।

आस्था कुंज पार्क गैंगरेप मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर लिया संज्ञान

नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने गुरुवार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी स्थित 'आस्था कुंज पार्क' में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। एडिशनल सेशन जज (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-पॉक्सो) स्वाति शर्मा ने पुलिस द्वारा दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए आरोपितों को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने (फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस) पर बहस के लिए अगली सुनवाई की तारीख एक दिसंबर तय की है। दिल्ली पुलिस ने 13 नवंबर को इस मामले में तीनों आरोपितों मोहम्मद आसिफ, हेमंत सिंह और मुकेश सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस की इस रिपोर्ट में लगभग 450 से 500 पन्नों के दस्तावेज शामिल हैं। जांच एजेंसी ने मामले को मजबूत बनाने के लिए 57 से 60 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें पीड़िता और घटना के समय उसके साथ मौजूद उसका दोस्त भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, चार्जशीट में आरोपितों की मोबाइल लोकेशन डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और घटनास्थल से जुटाए गए फॉरेंसिक व जैविक (बायोलॉजिकल) साक्ष्यों को प्रमुख आधार बनाया गया है। यह घटना 21 सितंबर की शाम सवा सात बजे से आठ बजे के बीच की है, जब तीनों आरोपितों ने लड़की और उसके 17 वर्षीय दोस्त को गेट नंबर 7 से पार्क में प्रवेश करते देखा।

डीटीसी बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें होंगी शामिल

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में 100 नई शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही है। इन बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली में बसों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 7,088 हो जाएगी, जिसमें 5,338 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें शामिल होंगी। इसके साथ ही दिल्ली देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाले शहर के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगी।

उन्होंने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इन 100 नई इलेक्ट्रिक बसों में 50 नौ मीटर और 50 बारह मीटर लंबाई वाली बसें शामिल होंगी। सुरक्षित, आरामदायक और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार ये लो-फ्लोर, वातानुकूलित बसें सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाओं सहित आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस होंगी। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करना दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम और स्वच्छ मोबिलिटी समाधानों के माध्यम से बदलने की दिल्ली सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के बस बेड़े का व्यापक और चरणबद्ध विस्तार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2028-29 तक दिल्ली में बसों की कुल संख्या लगभग 14,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर आधारित यह विस्तार सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी को मजबूत करने, बस सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने और स्वच्छ एवं टिकाऊ शहरी परिवहन के दीर्घकालिक विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंत्री बताया कि इलेक्ट्रिक बस बेड़े के विस्तार के साथ-साथ दिल्ली सरकार आनंद विहार आईएसबीटी और उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने जा रही है। प्रस्तावित सेवा से दिल्ली, गाजियाबाद और हापुड़ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को निर्धारित समय-सारिणी वाली, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था के तहत डीटीसी द्वारा आनंद विहार आईएसबीटी-हापुड़ मार्ग पर 12 पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय बस सेवा के तहत आनंद विहार आईएसबीटी से बसें सुबह 5:15 बजे से 8:55 बजे तक तथा इसके बाद सुबह 11:55 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक उपलब्ध होंगी। दोनों समयावधियों में बसों का संचालन 20 मिनट के अंतराल पर किया जाएगा। वापसी में हापुड़ से बसें सुबह 8:05 बजे से 11:45 बजे तक तथा इसके बाद दोपहर 2:45 बजे से शाम 6:25 बजे तक 20 मिनट के अंतराल पर संचालित होंगी।

सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले के दोनों आरोपितों की न्यायिक हिरासत 3 दिसंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के दो आरोपितों की न्यायिक हिरासत 3 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। एडिशनल सेशंस जज निशांत गर्ग ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। गुरुवार को इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश एक गवाह का बयान दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान इस मामले के दोनों आरोपितों तहसीन राजा और राजेश खिमजी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 9 सितंबर को इस मामले के आरोपित तहसीन राजा की जमानत याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी थी। उसके पहले भी कोर्ट ने 9 जून को तहसीन राजा की जमानत याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने कहा था कि आरोपित के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता और उसके भागने की संभावना को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है।

इस मामले में कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आरोपित तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 109(1) और आरोपित राजेश खिमजी के खिलाफ 109(1), 115(2), 221 और 132 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपित राजेश खिमजी ने एक सपने के बाद ऐसा किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने सपने में देखा कि एक शिवलिंग के बगल में बैठे कुत्ते ने उससे कहा कि दिल्ली में कुत्ते कष्ट में हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने फेसबुक पर वीडियो देखे जिसमें कुत्तों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जिम्मेदार ठहराते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे थे। चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि राजेश खिमजी ने मई में अयोध्या में बंदरों के सवाल पर भूख हड़ताल की थी। दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर 2025 को चार सौ पेजों की चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपितों राजेश खिमजी और तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, लोकसेवक के काम में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजेश खिमजी आवारा कुत्तों को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रुख से नाराज था। उच्चतम न्यायालय ने 11 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। इस फैसले का रेखा गुप्ता ने पुरजोर समर्थन किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इससे नाराज राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त 2025 को उस समय हमला किया जब वो जन सुनवाई कर रही थी।

26 नवंबर को दिल्ली कांग्रेस निकालेगी विशाल संविधान रक्षा मार्च, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

सद्भावना टुडे, मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत 26 नवंबर, संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी विशाल संविधान रक्षा मार्च निकालेगी। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा उनके खिलाफ अभियोजन चलाकर गिरफ्तारी की मांग उठाई है। मार्च के साथ ही वोट रक्षक अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सोमवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस के महासचिव (संगठन) एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने की। इसमें एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक एन. रघुवीरा रेड्डी, रुद्रा राजू और डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह सहित जिला अध्यक्षों, लोकसभा, जिला एवं विधानसभा पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। अनिल भारद्वाज ने कहा कि निर्वाचन आयोग के कथित संस्थागत कब्जे के विरोध तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापक संघर्ष किया है। इसी मेहनत का परिणाम एक नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली की सफलता रही।

उन्होंने बताया कि संविधान रक्षा मार्च की तैयारियों के लिए सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को 22 नवंबर तक अपने क्षेत्रों में बैठकें आयोजित करनी होंगी। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, वोट रक्षकों की नियुक्ति तथा अभियान की रूपरेखा तय की जाएगी। 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रदेश, जिला और ग्राम चौपाल स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जिला, ब्लॉक और मंडलम अध्यक्षों की अहम भूमिका होगी। भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य मतदाता सूची से कथित तौर पर हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम पुन: जुड़वाना और उनके मतदान अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान एवं करोड़ों नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार का हनन न हो। उन्होंने सुझाव दिया कि संविधान रक्षा मार्च की शुरुआत डॉ. भीमराव आंबेडकर अथवा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा से की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और 26 नवंबर का मार्च ऐतिहासिक बनाने के लिए दिल्ली के सभी क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी लोकसभा और जिला पर्यवेक्षक करेंगे, जबकि विधानसभा पर्यवेक्षक स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। अभियान से जुड़ी गतिविधियों, बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों, बूथ सत्यापन एवं मार्च की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के निर्देश भी दिए गए। अनिल भारद्वाज ने बताया कि वोट रक्षक कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक मंडल में हर बूथ पर कम से कम एक वोट रक्षक नियुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), बूथ समिति अध्यक्ष, युवा एवं अन्य अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी तथा अभियान से जुड़ने वाले नागरिक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्षों को प्रशिक्षण देकर वोट रक्षक अभियान को बूथ स्तर तक मजबूत बनाया जाएगा।

उत्तम नगर हत्याकांड मामले में आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित, 5 दिसंबर को सुनवाई होगी

नई दिल्ली। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज सुशांत चंगोट्रा ने 5 दिसंबर को आरोप तय करने पर फैसला सुनाने का आदेश दिया। आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपितों के वकीलों की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें पूरी कर ली गई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 5 दिसंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 22 मई को 17 आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है उनमें उमरद्दीन, कमरुद्दीन, जुम्माद्दीन, मुश्ताक, ताहिर, मुजफ्फर ऊर्फ मौजी, सलमा, शरीफन, सायरा बानो ऊर्फ काली, साहिल, समीर चौहान, शकील, मोहम्मद इस्माइल, इमामुद्दीन ऊर्फ लाला खान, अमीन, इमरान और रेहान शामिल हैं। कोर्ट ने इमरान ऊर्फ बंटी को गलती से गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं होने के बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी की जांच अधिकारी ने इमरान ऊर्फ बंटी को गलत रुप से हिरासत में रखने के बावजूद चार्जशीट दाखिल होने तक कोई कदम नहीं उठाया। दिल्ली पुलिस ने 6 मई 2026 को चार्जशीट दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपित बनाया। करीब पांच सौ पन्नों की चार्जशीट में हत्या, गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होना, दंगा करने, अनाधिकृत रुप से प्रवेश करने और एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है। दरअसल 4 मार्च 2026 को होली के दौरान तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी।

तिलक नगर गुरुद्वारे में बेअदबी के मामले पर सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल



नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) ने पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर स्थित शाहपुरा के गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी के मामले को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि गुरुद्वारे में बेअदबी की घटना दिल्ली के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि संगत ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर मामले को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि 15 नवंबर को तिलक नगर के शाहपुरा स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर संगत की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। संगत का कहना है कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने मामले को दबाने की कोशिश की और सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करने का प्रयास किया। भारद्वाज ने कहा कि बेअदबी गंभीर आपराधिक कृत्य है और इससे सांप्रदायिक सौहार्द भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या पुलिस को घटना की सूचना नहीं देना भी गंभीर अपराध है। उन्होंने बताया कि घटना के दो दिन बाद 17 नवंबर को मामले की जानकारी मिलने पर सिख समुदाय और संगत ने तिलक नगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधन के प्रति लोगों की नाराजगी सामने आई।

एमसीडी स्थायी समिति की बैठक में जनहित के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में बुधवार को जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में सफाई व्यवस्था, पार्किंग, सामुदायिक भवनों, निगम स्कूलों, आवारा कुत्तों के बंध्याकरण, जर्जर इमारतों तथा नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। स्थायी समिति अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पक्ष एवं विपक्ष के पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं और सुझाव रखने का अवसर दिया गया। बैठक के बाद अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई तथा समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

स्थायी समिति ने पिछले बजट में की गई सभी घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में पूरी हो चुकी घोषणाओं, जिनकी कार्ययोजना तैयार है तथा जिन पर कार्ययोजना बनाने की प्रक्रिया जारी है, उनका स्पष्ट विवरण देने को कहा गया। निगम के सभी सामुदायिक भवनों का सर्वे कराकर जर्जर एवं असुरक्षित भवनों की



सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष सत्या शर्मा ने अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा, ताकि आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्यों की योजना बनाई जा सके।

दिल्ली की सभी पार्किंग साइटों का सर्वे कराने पर जोर दिया गया। पार्किंग स्थलों के नियमानुसार संचालन, अवैध शुल्क वसूली तथा सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग की जांच करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निगम की पार्किंग सुविधाओं में जनप्रतिनिधियों को नियमानुसार नि:शुल्क पार्किंग सुविधा सुनिश्चित करने की बात कही गई।

स्कूलों के आसपास संचालित मीट की दुकानों पर नियंत्रण रखने तथा बिना लाइसेंस चल रही दुकानों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस मुद्दे पर अधिकारियों से नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में आवारा कुत्तों के बंध्याकरण अभियान को गति देने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को अभियान व्यवस्थित ढंग से चलाने तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैंक्वेट हॉल के कारण आसपास की सड़कों पर लगने वाले जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या पर भी चर्चा हुई। समिति ने पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था वाले बैंक्वेट हॉल को नियमानुसार लाइसेंस देने पर जोर दिया, ताकि यातायात बाधित होने की समस्या को कम किया जा सके। स्थायी समिति अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा ने कहा कि समिति जनहित के मुद्दों पर लोकतांत्रिक संवाद और सार्थक चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। पार्षदों द्वारा उठाए गए सभी विषयों को गंभीरता से सुना गया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

एक नजर

एसआईआर की समय सीमा बढ़ी, अब 22 दिसंबर को प्रकाशित होगी सूची

गुरुग्राम। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची संशोधन की समय-सारिणी में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। उपायुक्त उत्तम सिंह ने गुरुवार को बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, नवीनतम और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है अथवा उसके विवरण में कोई त्रुटि है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत 15 दिसंबर 2026 तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज करवाए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी नागरिक समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों से भी अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का लाभ उठाएं।

पुलिस बूथ के अंदर युवक से मारपीट, बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हुए आरोपी

फरीदाबाद। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। एनएचपीसी पुलिस बूथ के अंदर एक युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट किए जाने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि युवक की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। जांच के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। दयाल नगर निवासी युवक हीरालाल का आरोप है कि दो लोग उसे बुढिया नाले के पास से अपने साथ पुलिस बूथ के अंदर ले गए और वहां उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गया। आरोप है कि इसके बाद दोनों व्यक्ति उसे बूथ के अंदर ही छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उसे उपचार के लिए बीके अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित हीरालाल के अनुसार, वह कार पेंटर का काम करता है। बुधवार रात वह काम खत्म कर घर लौट रहा था। इसी दौरान बुढिया नाले के पास दो लोगों ने उसे आवाज देकर बुलाया। इसके बाद दोनों उसे अपने साथ एनएचपीसी पुलिस बूथ के अंदर ले गए। युवक का आरोप है कि बूथ के अंदर पहुंचते ही दोनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। पीड़ित के काफी देर तक घर नहीं पहुंचने और घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसकी तलाश करते हुए मौके पर पहुंचे। वहां युवक को घायल अवस्था में देखकर परिजन उसे तुरंत बीके अस्पताल लेकर गए, जहां उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया।

आठ किलो 20 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ युवक गिरफ्तार



पलवल। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) की फरीदाबाद यूनिट ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सौफता गांव से गुरुवार को एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आरिफ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से आठ किलो 20 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी अपने प्लॉट के बाहर खड़े होकर नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में था। एचएसएनसीबी फरीदाबाद यूनिट के इंचार्ज संग्राम सिंह के अनुसार, टीम को मानस राष्ट्रीय नशा विरोधी हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना मिली थी कि सौफता गांव निवासी आरिफ नशीले पदार्थों की बिक्री करता है। सूचना के आधार पर टीम ने आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। एएसआई महेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया। इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं बीडीपीओ नरेश कुमार की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी की पैंट की जेब से हेरोइन बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपी बरामद नशीले पदार्थ के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। टीम ने हेरोइन को कब्जे में लेकर सील कर दिया। मामले में गदपुरी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए गदपुरी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित 3500 परिवारों को बड़ी राहत



ग्रेटर नोएडा,एजेंसी। नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट) के स्टेज दो फेज वन में हुए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास जल्द हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने इन परिवारों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण के लिए शेष राशि आवंटित करने को स्वीकृति दे दी है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में शामिल नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व यमुना प्राधिकरण को भी अपनी अंशधारिता के सापेक्ष यह धनराशि देनी होगी। स्टेज दो फेज वन में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। इस जमीन अधिग्रहण से करीब साढ़े तीन हजार परिवार प्रभावित हैं। इन परिवारों का पुनर्वास फैलेदा बांगर और मॉडलपुर में प्रस्तावित है। इसके लिए सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर, जेवर बांगर, मेहंदीपुर बांगर, करौली बांगर, फैलेदा बांगर, धनुवास और तिरथली गांव की 189 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा रही है। इस जमीन के अधिग्रहण के लिए 8,913,456,831 रुपये में से 6,171,719,006 रुपये पूर्व में जारी किए गए थे। शेष 2,751,737,825 रुपये में से प्रदेश सरकार ने अपनी अंशधारिता के सापेक्ष 1,031,901,684 रुपये जारी करने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए जिला प्रशासन ने शासन से अनुरोध किया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए गठित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नायल) में प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण की अंशधारिता 37.5-37.5 प्रतिशत, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण की 12.5-12.5 प्रतिशत है। तीनों प्राधिकरण को भी कंपनी में शामिल अपनी अंशधारिता के सापेक्ष राशि जारी करनी होगी। शासन से मुआवजा राशि की स्वीकृति मिलने के बाद स्टेज 2 फेज वन के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की परियोजना में तेजी आएगी। प्रदेश सरकार की योजना स्टेज दो फेज वन में अधिग्रहित 1365 हेक्टेयर जमीन में एमआरओ विकसित करने की है। इससे जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ-साथ एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहालिंग का केंद्र भी बन जाएगा।

नाबालिग लड़की से विवाह करने पर पुरुष को भी हो सकती है दो साल की कैद सजा व जुर्माना

नूंह। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने गुरुवार को कहा कि बाल विवाह करवाना, इसमें सहयोग देना अथवा नाबालिग लड़की से विवाह करना कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। एडीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से 'आओ, मिलकर बनाएं बाल विवाह मुक्त भारत- बचपन खिलने दो, सपनों को उड़ने दो' अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की शिकार लड़की या लड़का बालिग होने के दो वर्ष के भीतर न्यायालय में आवेदन कर विवाह निरस्त करवा सकता है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। ज्योति ने बताया कि 27 नवंबर को बाल, कम उम्र एवं जबरन विवाह उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने सभी विभागों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

गुरुग्राम में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा, मौके से 17 युवक-युवतियां काबू

गुरुग्राम। अमेरिका व कनाडा के नागरिकों को एपल कस्टमर सर्विस का प्रतिनिधि बनकर साइबर ठगी का शिकार बनाने वाले एक संगठित फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का गुरुग्राम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने कॉल सेंटर से मौके पर 12 युवक व पांच युवतियों सहित 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 कंप्यूटर, छह लैपटॉप, पांच मोबाइल फोन तथा साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं।

गुरुवार को पुलिस थाना साइबर अपराध दक्षिण गुरुग्राम की पुलिस टीम को अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एक सूचना मिली। बताया गया कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड स्थित एम3एम डिजिटल ग्रीन बिल्डिंग में एक फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। इस कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिका के नागरिकों को एपल कस्टमर सर्विस का प्रतिनिधि बनकर फोन एवं डिजिटल माध्यम से संपर्क करके साइबर ठगी की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए निरीक्षक दिनेश कुमार ने पुलिस टीम के साथ बताए गए स्थान पर छापेमारी की। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां 12 युवक व पांच युवतियां कंप्यूटर सिस्टम पर हेडफोन लगाकर अंग्रेजी भाषा में बातचीत करते हुए मिले। आरोपियों द्वारा फर्जी तरीके से संचालित कॉल सेंटर में काम करते हुए विदेशी लोगों से अपना परिचय एपल कस्टमर सर्विस का प्रतिनिधि के रूप में करा रहे थे। कॉल सेंटर से काबू किए गए सभी 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक है। उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच है। गिरफ्तार आरोपियों में नितेश भारती निवासी जिला बलिया उत्तर प्रदेश, अनिमेश शर्मा निवासी शालीमार गार्डन गाजियाबाद, पैट्रिक रॉय निवासी कोलकाता, करण कुमार निवासी दिल्ली, एडी नगमलाई निवासी जिला तेनतिया हिल्स, मेघालय, आशीष निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली, तुषार मेहता निवासी गाजियाबाद, सूरज बरुई निवासी फरीदाबाद, अंकुश कुमार निवासी इस्माइलपुर फरीदाबाद, रितिक प्रजापति निवासी हरि नगर दिल्ली, सुखदीप सिंह निवासी मंडावली दिल्ली, अनीस मलिक निवासी जिला अलीगढ़, जंगमलू पानमेई निवासी इंफाल वेस्ट मणिपुर, चुइमेनाओ शिंगलाई निवासी मणिपुर, लीमा कैथरीन निवासी दीमापुर, नागालैंड, सैयदा फरदौ मेहफी निवासी गांधी बस्ती, गुवाहाटी, शाजिया खान निवासी ऐशबाग लखनऊ शामिल हैं।

ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से अधिक कमाई का झांसा देकर 20 लाख रुपये की ठगी

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे



नोएडा। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्धनगर नोएडा में थाना साइबर क्राइम में एक व्यक्ति ने बीती रात को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने अपने जाल में फंसा कर उनके साथ ठगी की है। आरोपितों ने ईकॉमर्स प्लेटफार्म पर रिसेल से होने वाले प्रॉफिट का स्कीम चार्ट भेजा तथा इसी प्लेटफार्म पर ऑनलाइन रि-सेल अकाउंट खोलने का लालच दिया। साइबर ठगों ने उनसे 20 लाख 36 हजार रुपये ठग लिया।

पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि बीती रात को तथागत अंकित ने थाना साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनके अनुसार 13 नवंबर को नायरा देसाई नामक एक महिला ने टेलीग्राम के माध्यम से उनसे संपर्क किया। उसने एक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर रिसेल से होने वाले फायदे के बारे में उनसे बातचीत की। उसने कहा कि इसी प्लेटफार्म पर ऑनलाइन रिसेल अकाउंट खोलने से उनका फायदा होगा। उसने कहा कि हम दोनों साथ मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। पीड़ित के अनुसार उसने महिला की बात पर विश्वास किया तथा धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। शुरुआती दौर में उन्हें ऑनलाइन प्लेटफार्म पर रिसेल करने से काफी अच्छा मुनाफा हुआ। उन्हें महिला की बात पर विश्वास हुआ तथा उन्होंने धीरे-धीरे करके 10 बार में 20 लाख 36 हजार रुपये ई-कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। जब उन्होंने अपनी रकम निकालनी चाही तो आरोपितों ने और रकम की डिमांड की। उसके बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।

गुरुग्राम को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त बनाने में भूमिका निभाएं कॉरपोरेट कंपनियां: राव इंद्रजीत सिंह



गुरुग्राम,एजेंसी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरुग्राम केवल हरियाणा ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक शहरों में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस शहर की तरक्की में यहां स्थापित राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में इन कंपनियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वे अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुवार को नेस्ले इंडिया की सीएसआर पहल के तहत शुरू किए गए क्लीन कॉरिडोर गुरुग्राम अभियान के शुभारंभ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

राव इंद्रजीत सिंह ने नेस्ले इंडिया की ओर से भेंट किए गए स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने पूर्व अपने संबोधन में कहा कि ऐसी पहल केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अन्य कॉरपोरेट संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को भी इससे प्रेरणा लेकर आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में प्रदूषण और यातायात जैसी चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। इनका समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें औद्योगिक संस्थानों, कॉरपोरेट जगत और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है और प्रदेश के कुल राजस्व में लगभग 65 प्रतिशत योगदान इस क्षेत्र से आता है। इसी प्रकार प्रदेश की कुल बिजली खपत के बिलों में भी गुरुग्राम की हिस्सेदारी लगभग 42 प्रतिशत है।

यह आंकड़े इस शहर की आर्थिक महत्ता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों की तरह गुरुग्राम भी देश के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखता है और हरियाणा का गौरव बढ़ाता है। ऐसे में यहां की बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नेस्ले इंडिया की ओर से एंबियंस मॉल से राजीव चौक तक राष्ट्रीय राजमार्ग के 16 किलोमीटर लंबे हिस्से को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रतिदिन दो बार मशीनीकृत स्वीपिंग के माध्यम से सड़क की सफाई की जाएगी। धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव और आठ कर्मचारियों की टीम द्वारा प्रतिदिन सुबह नौ से शाम पांच बजे तक कचरे का संग्रहण किया जाएगा।

दिहाना स्कूल की छात्राओं ने प्रयोगशाला में सीखी पानी की शुद्धता जांचने की वैज्ञानिक प्रक्रिया

नूंह। विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक और वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिहाना के विज्ञान संकाय की छात्राओं ने नूंह स्थित जिला पेयजल जांच प्रयोगशाला का गुरुवार को शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान छात्राओं ने पेयजल की गुणवत्ता जांचने की विभिन्न वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की।

प्रयोगशाला में जिला रसायनशास्त्री ताहिर हुसैन ने छात्राओं को पानी की गुणवत्ता जांचने के भौतिक एवं रासायनिक मानकों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से पेयजल की शुद्धता और गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। उन्होंने छात्राओं को पानी की जांच की प्रक्रिया और दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता से भी अवगत कराया। इस

सांस्कृतिक संध्या में भारत की 11 रानियों के रूप में महिलाओं का रहा जलवा

गुरुग्राम। माहेश्वरी सभा गुरुग्राम महिला मंडल एवं युवा संगठन के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को दीपावली मिलन समारोह एवं सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। यहां ओल्ड दिल्ली रोड स्थित अमित महल सेक्टर-14 में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, गणेश वंदना और महेश वंदना से हुआ। भारत की 11 रानियों की भूमिका में महिलाओं का जलवा रहा।

माहेश्वरी सभा गुरुग्राम अध्यक्ष महेश जाखेटिया के दीपावली शुभकामना संदेश के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसे जेन-जी मुकुंज मूंदड़ा, प्रियांशी लाहोटी, मीनल लड्ढा एवं आरव माहेश्वरी द्वारा मंच से पहली बार संचालित किया गया। प्रमुख अतिथियों में किरण लड्ढा (महासचिव, अखिल भारतवर्षीय महिला मंडल) एसएन चांडक (चेयरमैन, शील बायोटेक), हरि ओम गांधी (डीआईजी सीआईएसएफ), संदीप परवाल (फाउंडर, एसपीए फाइनेंशियल एडवाइजर) की गरिमामयी उपस्थिति में इस कार्यक्रम में लगभग 600 माहेश्वरी बंधुओं ने भाग लिया। रामायण को कोरियोग्राफर प्रीति मालानी ने महिला सदस्यों के साथ बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। हेरिटेज क्वीन ऑफ इंडिया में भारत की 11 रानियों का प्रस्तुतीकरण एक अलग अनुभव रहा, जहां समाज की महिला सदस्यों ने अपने किरदारों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। हेरिटेज क्वीन कार्यक्रम सरोज दम्माणी द्वारा निर्देशित किया गया एवं मोनिका द्वारा संचालित किया गया। अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां सांस्कृतिक सचिव आशुतोष माहेश्वरी के निर्देशन में हुई। सात वर्षों के पश्चात समाज की स्मारिका को प्रकाशित किया गया, जिसका विमोचन जिला सभा उपाध्यक्ष आशीष राठी द्वारा किया गया। माहेश्वरी समाज गुडगांव की वेबसाइट को जिला सभा सचिव संजय सारडा एवं आदित्य जाखेटिया द्वारा लॉन्च किया गया। सुनीता माहेश्वरी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम का सभी ने आनंद लिया।

सिकरावा में 'वोट बचाओ-देश बचाओ' चौपाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ ने की शिरकत

नूंह,एजेंसी। नूंह जिले के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के गांव सिकरावा में जिला कांग्रेस कमेटी नूंह की ओर से 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान के तहत गुरुवार को चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक शहीदा खान ने की, जबकि आयोजन की जिम्मेदारी ब्लॉक अध्यक्ष मुबारिक मलिक ने संभाली। चौपाल के दौरान ग्रामीणों को मतदाता सूची से कथित रूप से गलत तरीके से नाम काटे जाने के मुद्दे पर जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची से कट जाता है तो उसे दोबारा जुड़वाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक का वोट महत्वपूर्ण है। मताधिकार की सुरक्षा और मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने अभियान के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करने की बात कही। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहीदा खान ने कहा कि कांग्रेस का संकल्प है कि गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचकर प्रत्येक नागरिक को उसके वोट के अधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए मताधिकार से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाई जाएगी, क्योंकि वोट की ताकत ही लोकतंत्र की असली ताकत है। कार्यक्रम में पूर्व प्रत्याशी हाजी अख्तर हुसैन, हाजी सुबराती खान, यूथ अध्यक्ष मुबीन तेड, मकसूद सिकरावा, साहब खान पटवारी, ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण, जमशेद खान व सैफुल्लाह खान, इंटैक जिलाध्यक्ष आसिफ, इरशाद चेयरमैन, आरिफ लुहिंगा, इम्तियाज अली, हाजी खुर्शीद, हासिम गंगवानी, अंजुम पार्षद, हाजी अब्बास जयसिंहपुर, शाकिर खान, लियाकत अली, तौसीफ खान, रफीक चेयरमैन, उस्मान गंगवानी, महमूदा चेयरमैन, रत्ती प्रधान, खुर्शीद खान और मास्टर नूरुद्दीन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नाइजीरियाई प्रतिनिधिमंडल को चंदू गांव में भायी महिलाओं की बेकरी

गुरुग्राम,एजेंसी। नाइजीरिया से आए 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गुरुग्राम के गांव चंदू का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षितिज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित बेकरी इकाई का अवलोकन किया। इसी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण महिलाओं की मेहनत और उनके लिए सरकार के प्रयास अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गए। प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के कार्यों तथा उद्यमशीलता की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल के गुरुग्राम आगमन पर जिला परिषद के सीईओ सुमित कुमार ने उनका स्वागत किया।

प्रतिनिधिमंडल में नाइजीरिया के मानवतावादी मामलों एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव ओलुसान्या ओलुबुनमी, सरकारी नकद सहायता कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधक अलहसन अब्दुल्लाही इमाम, केंद्र सरकार के लेखा विभाग में परियोजना वित्त प्रबंधन के निदेशक लुका जोशुआ कादमी तथा राष्ट्रीय सामाजिक निवेश कार्यक्रम के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गिदे जमीलू सहित विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।



दौरे के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिनिधिमंडल को बेकरी इकाई की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। महिलाओं ने आटा गूंथने, विभिन्न बेकरी उत्पाद तैयार करने, उनकी पैकेजिंग, बिलिंग से लेकर मार्केटिंग तक की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने महिलाओं द्वारा तैयार किए गए बेकरी उत्पादों का स्वाद भी चखा और उनसे संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। उन्होंने इस बात की सराहना की कि ग्रामीण महिलाएं सामूहिक प्रयासों और उद्यमिता के माध्यम से न केवल अपनी आजीविका को मजबूत कर रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार एवं प्रेरणा का माध्यम बन रही हैं। इस अवसर पर हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है।

आसियान मंचः भारत का दबदबा, मोदी की कूटनीतिक गूंज

ललित गर्ग



किसी देश का वैश्विक प्रभाव केवल उसकी आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता या जनसंख्या से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि विश्व की महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसकी बात को कितनी गंभीरता से सुनती हैं। आज भारत इसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों के संगठन आसियान का भारत सदस्य नहीं है, फिर भी उसके सर्वोच्च सम्मेलनों में भारत की उपस्थिति जिस सम्मान और अपेक्षा के साथ होती है, वह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का महत्वपूर्ण संकेत है। हाल ही में फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुए 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भागीदारी ने इस बदलती तस्वीर को और स्पष्ट किया है। यह दृश्य अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान की भविष्य-चर्चा में भारत को अलग रखकर क्षेत्रीय समीकरणों की कल्पना करना कठिन होता जा रहा है। यही भारत की कूटनीतिक यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 1991 की 'लुक ईस्ट' नीति से शुरू हुई यात्रा 2014 में 'एक्ट ईस्ट' नीति और अब व्यापक हिंद-प्रशांत दृष्टि तक पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के केंद्र में बताया है।

आसियान केवल भौगोलिक समूह नहीं है। यह आर्थिक शक्ति, समुद्री मार्गों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और हिंद-प्रशांत की रणनीतिक राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और तिमोर-लेस्ते जैसे देश भारत के लिए व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक संपर्क की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मनीला में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत और आसियान को प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग को आधार बनाकर शांति, स्थिरता और विकास का वातावरण तैयार करना चाहिए। उन्होंने मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और आसियान की एकता तथा केंद्रीयता को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह केवल कूटनीतिक भाषा नहीं है। इसके पीछे भारत की दीर्घकालीन रणनीति है- ऐसा हिंद-प्रशांत जिसमें किसी एक शक्ति का वर्चस्व न हो, छोटे देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने की जगह मिले और समुद्री मार्ग खुले रहें। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक विशिष्ट पक्ष यह है कि उन्होंने भारत को केवल 'बड़ा बाजार' या 'उभरती अर्थव्यवस्था' के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। मनीला में इसका प्रमाण अनेक द्विपक्षीय मुलाकातों में दिखाई दिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ मोदी ने रक्षा, अंतरिक्ष, रेल, वित्तीय तकनीक तथा व्यापार और निवेश में सहयोग की प्रगति पर चर्चा की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ डिजिटल क्षेत्र, कौशल, संपर्क, स्वास्थ्य, रक्षा-सुरक्षा और आर्थिक सहयोग की समीक्षा हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। मोदी की विदेश नीति का संदेश साफ है-भारत संबंधों का केवल दर्शक नहीं, बल्कि संबंधों की नई संरचना का सक्रिय निर्माता बनना चाहता है। इस पूरी यात्रा में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की राजनीतिक दृष्टि को वैश्विक कूटनीतिक संवाद में ठोस स्वरूप देने में जयशंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे केवल विदेश मंत्रालय के प्रशासक नहीं, बल्कि बदलती विश्व-व्यवस्था को समझने वाले रणनीतिक चिंतक के रूप में भारत की विदेश नीति का प्रभावी चेहरा बने हैं। भारत की विदेश नीति में आज एक साथ अमेरिका, रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के साथ संबंधों को संतुलित रखने की क्षमता दिखाई देती है। यह संतुलन किसी एक खेमे में जाने के बजाय भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंधों को आकार देने की नीति को दर्शाता है। जयशंकर की कूटनीति का मूल संदेश भी यही रहा है कि भारत किसी शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों और अपनी सभ्यतागत दृष्टि के आधार पर विश्व से संबंध बनाएगा। प्रधानमंत्री की राजनीतिक सक्रियता और विदेश मंत्री की रणनीतिक कूटनीति का यह संयोजन भारत की विदेश नीति को अधिक प्रभावशाली बना रहा है।

मनीला सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति ने भी इस यात्रा को विशेष महत्व दिया। 17 नवंबर को मनीला में पहली बार क्वाड नेताओं का शिखर-स्तरीय संवाद हुआ, जिसमें मोदी, ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची साने और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज शामिल हुए। इस घटनाक्रम का संदेश बहुत व्यापक है। भारत एक ओर आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के माध्यम से हिंद-प्रशांत की रणनीतिक संरचना को भी मजबूत कर रहा है। इसका अर्थ किसी देश के विरुद्ध मोर्चेबंदी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखलाओं, महत्वपूर्ण खनिजों, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग में साझेदारी को बढ़ाना है। यहां मोदी की विदेश नीति का एक नया आयाम दिखाई देता है-भारत अब शक्ति-संतुलन का निष्क्रिय हिस्सा नहीं, बल्कि शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने वाला केंद्र बनना चाहता है। आसियान देशों के लिए चीन एक बड़ा आर्थिक साझेदार है, लेकिन उसके साथ समुद्री और रणनीतिक विवाद भी हैं। दक्षिण चीन सागर में तनाव, आर्थिक निर्भरता और क्षेत्रीय प्रभाव की प्रतिस्पर्धा के बीच आसियान देश किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहते। यही भारत के लिए बड़ा अवसर है। भारत को चीन का विकल्प बनने की जल्दबाजी करने के बजाय विश्वसनीय विकल्प बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए व्यापार घाटे को कम करना, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और भारत-आसियान संपर्क परियोजनाओं को तेजी देना आवश्यक है। मनीला में घोषित समुद्री सहयोग योजना, साइबर प्रशिक्षण, अंतरिक्ष सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा, युवाओं और स्टार्ट-अप सहयोग तथा नालंदा में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जैसी पहलें इसी नई दिशा की ओर संकेत करती हैं। भारत-आसियान संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती व्यापार असंतुलन है। केवल आयात बढ़ाना या बाजार खोलना पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय उद्योग को आसियान के बाजारों में अधिक आक्रामक, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी उपस्थिति बनानी होगी। मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत की ताकत केवल अर्थव्यवस्था नहीं, उसकी संस्कृति भी है। रामायण की परंपरा से लेकर बौद्ध दर्शन, भारतीय भाषाओं, योग, आयुर्वेद और समुद्री व्यापार की प्राचीन स्मृतियों तक भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सदियों पुराना संबंध है। आज आवश्यकता इस सभ्यतागत पूंजी को आधुनिक आर्थिक और तकनीकी साझेदारी से जोड़ने की है। मनीला सम्मेलन की सबसे बड़ी सीख यह है कि भारत को आसियान को केवल विदेश नीति की एक इकाई के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसे भारत के आर्थिक, सामरिक और सभ्यतागत पुनर्संपर्क का द्वार बनाना चाहिए। यदि भारत व्यापार, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और संपर्क के साथ संस्कृति, शिक्षा और युवाओं को जोड़ देता है, तो आसियान भारत के लिए केवल एक बाजार नहीं रहेगा, वह भारत के हिंद-प्रशांत भविष्य का स्वाभाविक साझेदार बन सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जिस आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंचों पर भारत की बात रखते हैं, उसके पीछे वर्षों की कूटनीतिक मेहनत, संस्थागत तैयारी और विदेश मंत्रालय की निरंतर सक्रियता है। आसियान में भारत की स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि भारत की आवाज अब केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि उस पर ध्यान भी दिया जाता है। भारत की विदेश नीति का अगला लक्ष्य केवल विश्व में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य यह होना चाहिए कि विश्व की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका हो। आसियान का मनीला मंच इसी बदलते भारत की तस्वीर सामने रखता है-भारत अब दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देने वाला देश नहीं रहा, वह ऐसी शक्ति बन रहा है जिसके साथ दुनिया अपने भविष्य की रणनीति पर विचार करना चाहती है। यही मोदी युग की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि और आने वाले भारत की सबसे बड़ी संभावना है।

वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनकी समस्याओं को हल करना, उनके कल्याण के लिए काम करना तथा अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। बाल दिवस दुनियाभर में 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और अनेक देशों में इसे मनाने की तारीखें अलग-अलग हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर माह किसी न किसी देश में बाल दिवस का आयोजन होता है। संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर 1954 को 'विश्व बाल दिवस' मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य यही था कि इस विशेष दिन के माध्यम से अलग-अलग देशों के बच्चे एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें, जिससे उनके बीच आपसी समझ तथा एकता की भावना मजबूत हो सके। सर्वप्रथम बाल दिवस जिनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्वभर में अक्टूबर 1953 में मनाया गया। विश्वभर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार वीके कृष्ण मेनन का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1954 में अपनाया। संयुक्त राष्ट्र ने विश्वभर के तमाम देशों से अपील की कि वे अपनी परम्पराओं, संस्कृति तथा धर्म के अनुसार अपने लिए कोई एक ऐसा दिन सुनिश्चित करें, जो सिर्फ बच्चों को ही समर्पित हो। वैसे तो बाल दिवस मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1925 से ही हो गई थी लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो इसे दुनियाभर में मान्यता मिली 1953 में।

सींचना होगा बच्चों के मधुवन को

योगेश कुमार गोयल

(विश्व बाल दिवस/20 नवंबर/विशेष)



बाल दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। बच्चों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस हमें बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष यह दिवस 'मेरा दिन, मेरे अधिकार, मेरा भविष्य' विषय के साथ मनाया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि सभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण सहित उनके मौलिक अधिकारों तक पहुंच हो। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनकी समस्याओं को हल करना, उनके कल्याण के लिए काम करना तथा अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। बाल दिवस दुनियाभर में 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है और अनेक देशों में इसे मनाने की तारीखें अलग-अलग हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर माह किसी न किसी देश में बाल दिवस का आयोजन होता है।

संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर 1954 को 'विश्व बाल दिवस' मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य यही था कि इस विशेष दिन के माध्यम से अलग-अलग देशों के बच्चे एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें, जिससे उनके बीच आपसी समझ तथा एकता की भावना मजबूत हो सके। सर्वप्रथम बाल दिवस जिनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्वभर में अक्टूबर 1953 में मनाया गया। विश्वभर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार वीके कृष्ण मेनन का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1954 में अपनाया। संयुक्त राष्ट्र ने विश्वभर के तमाम देशों से अपील की कि वे अपनी परम्पराओं, संस्कृति तथा धर्म के अनुसार अपने लिए कोई एक ऐसा दिन सुनिश्चित करें, जो सिर्फ बच्चों को ही समर्पित हो। वैसे तो बाल दिवस मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1925 से ही हो गई थी लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो इसे दुनियाभर में मान्यता मिली 1953 में। दुनियाभर में बाल दिवस के माध्यम से लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल मजदूरी इत्यादि बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले बाल दिवस तुर्किये में मनाया गया था। आइए देखते हैं कि दुनियाभर में किन देशों द्वारा कब बाल दिवस मनाया जाता है। जनवरी के पहले शुक्रवार को बहामास , 11 जनवरी को ट्यूनिशिया, जनवरी के दूसरे शनिवार को थाईलैंड, फरवरी के दूसरे रविवार को कुक द्वीप समूह, नाउरू, निउए, टोकेलौ तथा केमन द्वीप समूह, 13 फरवरी को म्यांमार, मार्च के पहले रविवार को न्यूजीलैंड, 17 मार्च को बांग्लादेश, 4 अप्रैल को ताइपे, हांगकांग, 5 अप्रैल को फिलीस्तीन, 12 अप्रैल को बोलिविया तथा हैती, 23 अप्रैल को तुर्किये, 30 अप्रैल को मेक्सिको, 5 मई को दक्षिण कोरिया तथा जापान, मई के दूसरे रविवार को स्पेन तथा यूके, 10 मई को मालदीव, 17 मई को नार्वे, 27 मई को नाईजीरिया, मई के आखरी रविवार को हंगरी, 1 जून को चीन सहित कई देशों में बाल संरक्षण दिवस के रूप में, 1 जुलाई को पाकिस्तान, जुलाई के तीसरे रविवार को क्यूबा, पनामा, वेनेजुएला, 23 जुलाई को इंडोनेशिया, अगस्त के पहले रविवार को उरुग्वे, 16 अगस्त को पैराग्वे, अगस्त के तीसरे रविवार को अर्जेन्टीना तथा पेरू, 9 सितम्बर कोस्टा रीका, 10 सितम्बर को हौण्डुरस, 14 सितम्बर को नेपाल, 20 सितम्बर को आस्ट्रिया तथा जर्मनी, 25 सितम्बर को नीदरलैंड, 1 अक्टूबर को अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला तथा श्रीलंका, अक्टूबर के पहले बुधवार को चिली, अक्टूबर के पहले शुक्रवार को सिंगापुर, 8 अक्टूबर को ईरान, 12 अक्टूबर को ब्राजील, अक्टूबर के चौथे शनिवार को मलेशिया, अक्टूबर के चौथे रविवार को आस्ट्रेलिया, नवंबर के पहले शनिवार को दक्षिण अफ्रीका, 20 नवंबर को अजरबैजान, कनाडा, साइप्रस, मिस्र, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आयरलैंड, इजराइल, केन्या, मैसिडोनिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, सर्बिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद व टोबेगो, 5 दिसम्बर को सूरीनाम, 23 दिसम्बर को सूडान तथा 25 दिसम्बर कांगो गणराज्य, कैमरून तथा भूमध्यरेखीय गिनी में बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। बहरहाल, विश्व बाल दिवस हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि बच्चों का भविष्य उनके आज पर निर्भर करता है, जिसके लिए हमें ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बाल श्रम और शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बच्चों को उनकी प्रतिभा को निखारने के पर्याप्त अवसर मिलें, उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और पोषित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। भारत में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू हैं, जिनमें बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो एक्ट 2012 प्रमुख रूप से शामिल हैं। मिड-डे मील योजना और आंगनवाड़ी सेवा जैसी योजनाएं भी बच्चों के पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी-अपनी सहूलियत के आधार पर विभिन्न देश भले ही अलग-अलग तारीखों पर बाल दिवस मनाते हैं पर हर जगह बाल दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि इसके जरिये लोगों को बच्चों के अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके और बच्चों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके।

विचार

वैश्विक बाजार, भारत की निर्यात शक्ति का विस्तार

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने अपने निर्यात के मोर्चे पर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। कहना होगा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में भारत के निर्यात ने प्रमुख मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) साझेदारों और दुनिया के बड़े व्यापारिक बाजारों में व्यापक विस्तार किया है। दक्षिण-पूर्व एशिया से लेकर यूरोप और पूर्वी एशिया तक भारतीय उत्पादों की बढ़ती पहुंच का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आसियान देशों को भारत का निर्यात 58 प्रतिशत उछलकर 28.06 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। वहीं, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के साझेदार देशों को निर्यात में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 15.29 अरब डॉलर हो गया। यूरोपीय संघ को भी भारत का निर्यात पांच प्रतिशत बढ़कर 38.79 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत के निर्यात प्रदर्शन की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धियों में सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया और ओमान जैसे बाजारों में दर्ज दो अंकों की वृद्धि शामिल है। सिंगापुर को निर्यात 103 प्रतिशत बढ़कर 11.07 अरब डॉलर हो गया, जबकि मलेशिया में 83 प्रतिशत और श्रीलंका में 73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ओमान को निर्यात भी 47 प्रतिशत बढ़कर 3.29 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि भारत अपने पारंपरिक व्यापारिक बाजारों के साथ नए और तेजी से विकसित हो रहे बाजारों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति बना रहा है। भारत के निर्यात विस्तार में दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) सबसे महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र के रूप में सामने आया है। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-सितंबर अवधि में आसियान देशों को भारत का निर्यात 17.75 अरब डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2026-27 की समान अवधि में 58 प्रतिशत बढ़कर 28.06 अरब डॉलर हो गया। इस वृद्धि में सिंगापुर और मलेशिया की विशेष भूमिका रही। सिंगापुर को भारत का निर्यात 5.45 अरब डॉलर से बढ़कर 11.07 अरब डॉलर हो गया। इस तरह एक वर्ष में निर्यात दोगुने से भी अधिक बढ़ा। मलेशिया के बाजार में भी भारतीय उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय तेजी रही। यहां निर्यात 3.05 अरब डॉलर से 83 प्रतिशत बढ़कर 5.58 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वियतनाम को निर्यात 36 प्रतिशत बढ़कर 3.83 अरब डॉलर और इंडोनेशिया को 36 प्रतिशत बढ़कर 2.98 अरब डॉलर हो गया। थाईलैंड भी भारत के महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्यों में शामिल रहा, जहां 2.65 अरब डॉलर का निर्यात दर्ज किया गया। वस्तुतः आज आसियान देशों के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक संबंधों का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। इस बाजार में भारतीय निर्यात की बढ़ती हिस्सेदारी भविष्य में व्यापारिक सहयोग और औद्योगिक साझेदारी के नए अवसर पैदा कर सकती है। इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका की बड़ी छलांग दिखाई दी है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में यह मजबूती का पर्याय है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के साझेदारों को भारत का निर्यात 22 प्रतिशत बढ़कर 15.29 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 12.55 अरब डॉलर था। जिसमें कि श्रीलंका सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शामिल रहा। यहां भारतीय निर्यात 2.28 अरब डॉलर से 73 प्रतिशत बढ़कर 3.94 अरब डॉलर हो गया। नेपाल को निर्यात 19 प्रतिशत बढ़कर 4.37 अरब डॉलर और भूटान को 16 प्रतिशत बढ़कर 711.4 मिलियन डॉलर तक पहुंचा। मालदीव के बाजार में भी 52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और निर्यात 337.4 मिलियन डॉलर हो गया। बांग्लादेश 5.66 अरब डॉलर के निर्यात के साथ साफ्टा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा। पूर्वी एशिया के विकसित औद्योगिक बाजारों में भी भारत के निर्यात को गति मिली है। जापान को निर्यात 40 प्रतिशत बढ़कर 4.10 अरब डॉलर हो गया, जबकि दक्षिण कोरिया को निर्यात में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 3.91 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इन दोनों बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती पहुंच भारत के औद्योगिक और व्यापारिक संबंधों के विस्तार का संकेत है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों में निर्यात वृद्धि का महत्व इसलिए भी है कि ये देश वैश्विक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और उन्नत विनिर्माण के बड़े केंद्र हैं। इन बाजारों में भारतीय कंपनियों के लिए व्यापारिक अवसरों का विस्तार देश की उत्पादन क्षमता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। यूरोपीय संघ भारत के बड़े निर्यात बाजारों में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 36.97 अरब डॉलर से पांच प्रतिशत बढ़कर 38.79 अरब डॉलर हो गया।

एक नजर

सुशासन दिवस-नीतीश संवाद की तैयारी में जुटी जदयू, हर वार्ड से 25 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य



दरभंगा,एजेंसी। आगामी 24 नवंबर को आयोजित होने वाले सुशासन दिवस-नीतीश संवाद कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जदयू दरभंगा नगर जिला में संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम में अधिकाधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के साथ लालबाग और रहमगंज सेक्टर में बैठक आयोजित की गई। लालबाग सेक्टर अध्यक्ष दीपक ज्योति गुप्ता तथा रहमगंज सेक्टर अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठकों में कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं की सहभागिता को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जदयू नगर जिला अध्यक्ष माधव झा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 से बिहार में विकास और सुशासन का नया दौर शुरू हुआ। उनके कार्यकाल में राज्य ने प्रगति की दिशा में कई कदम बढ़ाए। इसी तारीख की स्मृति में पूरे बिहार में सुशासन दिवस-नीतीश संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय के साथ जुटना होगा। वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज साह ने सेक्टर अध्यक्षों से प्रत्येक वार्ड से कम से कम 25 कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बैठक में पवन श्रीवास्तव, मनोज कुमार ठाकुर, डॉ. रामजी विश्वकर्मा, किशोर कुमार मल्लिक, ईश्वर प्रसाद सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, हबीब असगर, रुस्तम, अशोक ठाकुर, सलाउद्दीन, इकबाल रायन, अशरफ शेख, सद्दाक, नूर आलम एवं विनोद यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

निरुआ स्कूल के समीप बाइक सवार तीन बदमाशों ने युवक को मारी गोली



सीवान। महाराजगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। गुरुवार को बाजार से खरीदारी कर घर लौट रहे एक युवक को बाइक सवार तीन बदमाशों ने निरुआ स्कूल के समीप गोली मार दी। गोली युवक के हाथ में लगी, जिससे वह घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गयी। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गयी। घायल की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के रढ़िया गांव निवासी वकील राय के पुत्र बंटी कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बंटी कुमार बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान निरुआ स्कूल के समीप एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे तीन युवकों ने उन्हें निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली उनके हाथ में जा लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गये। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को इलाज के लिए महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे सीवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक ने गोली मारने के आरोप में पुलिस को तीन लोगों के नाम बताए हैं। हालांकि, आरोपितों की संलिप्तता और घटना के पीछे की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गयी है। पुलिस आरोपितों की पहचान, गिरफ्तारी और गोलीबारी के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है।

महिला सशक्तिकरण के लिए बेटों को भी संस्कारित करना जरूरी : डॉ. धर्मशिला गुप्ता

दरभंगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश में कई महत्वपूर्ण पहल हुई हैं, लेकिन सामाजिक समानता और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बेटियों को सशक्त बनाने के साथ बेटों को भी संस्कारित करना जरूरी है। यह बातें राज्यसभा सांसद डॉ. धर्मशिला गुप्ता ने गुरुवार को सीएम कॉलेज में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में कहीं। कॉलेज के वूमेन्स सेल की ओर से 'ब्रेकिंग बैरियर्स : वीमेंस इंपावरमेंट एंड बियांड' विषय पर आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी और महिला शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ नेतृत्व की भूमिका निभाने के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए परिवार और समाज की सोच में भी बदलाव जरूरी है। विशिष्ट अतिथि डॉ. पूनम कुमारी मिश्रा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की वास्तविक शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। अलीगढ़ की डॉ. आयशा मुनीरा रशीद ने महिलाओं के कौशल विकास को आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार बताया। वहीं डॉ. निभा सिंह ने कार्यक्षेत्र में लैंगिक विभाजन समाप्त करने तथा डॉ. प्रणव कुमार प्रभाकर ने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। अध्यक्षीय संबोधन में कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मुश्ताक अहमद ने कहा कि महिला-पुरुष समानता संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सामाजिक रूढ़ियों और बाधाओं के कारण आज भी महिला सशक्तिकरण पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता बनी हुई है। इस अवसर पर संगोष्ठी की स्मारिका का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक, शिक्षाविद् तथा विभिन्न संस्थानों से आए प्रतिभागी उपस्थित थे।

बिहार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाकर निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाना है : मुख्यमंत्री

पटना,एजेंसी। उद्योग विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला 'लेवरेजिंग एफटीएज आउटरीच प्रोग्राम' का उद्घाटन गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाकर निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाना है। एक होटल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अब तक बिजली, सड़क, आधारभूत संरचना एवं अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया गया है। अब बिहार को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़कर उद्योग, व्यापार और निर्यात को नई ऊंचाई प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बिहार की दो प्रमुख चुनौतियां आबादी और पानी रही हैं। हमें इन दोनों को आनेवाले 10 वर्षों में अपनी ताकत बनाना है। इसके लिए आबादी को व्यवस्थित रूप से संगठित करने तथा जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बिहार में सड़क एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण से बिहार के सात-आठ जिले जुड़ेंगे। सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है, ताकि बिहार का संपर्क अंतरराष्ट्रीय बाजार से बेहतर हो सके। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि नगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज एवं किशनगंज जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर हवाई अड्डों के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अनुरूप रन-



वे एवं अन्य सुविधाओं से सुसज्जित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बिहार का मखाना आज सुपरफूड के रूप में देश-दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। बिहार से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत है। मखाना के साथ-साथ लीची और मक्का के उत्पादन में भी बिहार अग्रणी है। मक्का का उपयोग एथेनॉल उत्पादन में भी किया जा रहा है। राज्य के इन विशिष्ट उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए बेहतर ब्रांडिंग, गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं निर्यात व्यवस्था विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है और राज्य लगभग 10 प्रतिशत राजस्व का योगदान करता है। ऐसे में राष्ट्रीय व्यापार एवं बाजार में भी बिहार की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर काम करना होगा। आयात-निर्यात को बढ़ावा देना, नए बाजारों की पहचान करना तथा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाना आवश्यक है। 31 देशों में मौजूद बिहार चैप्टर के सहयोग से ऐसे देशों के बाजारों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जहां भारतीय उत्पादों को बेहतर अवसर एवं कम शुल्क का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नौजवानों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने का सबसे प्रभावी रास्ता उद्योगों का विकास है। उन्होंने बताया कि बिहार में ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया गया है। राज्य में 12 सैटेलाईट टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं। इन शहरों में रेलवे कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार का समृद्ध होना आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका एवं एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया।

गोवा फिल्म फेस्टिवल में फिल्म नीति पर होगी चर्चा, बिहार पवेलियन पर मिलेगी जानकारी

गोवा। गोवा में 20 नवंबर से शुरू हो रहे 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) में बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम के प्रबंध निदेशक प्रणव कुमार (आईएएस) के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 का प्रचार करेगी एवं फिल्म निर्माताओं से बातचीत कर राज्य में निवेश की संभावनाओं की तलाश करेगी।

इस उद्देश्य से बिहार फिल्म निगम की ओर से फिल्म बाजार में बिहार पवेलियन स्थापित किया गया है। यहां फिल्म निर्माता बिहार फिल्म निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों से फिल्म नीति से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के साथ ही फिल्म उद्योग में नवाचार पर चर्चा कर सकते हैं। विगत वर्षों में फिल्म बाजार फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। प्रणव कुमार ने कहा कि बड़े प्रोडक्शन हाउस की जरूरत को समझकर उनके अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने सदस्यों को शुभकामनाएं दीं। फिल्म निगम की महाप्रबंधक रूबी ने फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने की तैयारियों की समीक्षा की और संतोष व्यक्त किया। फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 से 24 नवंबर तक लगने वाले फिल्म बाजार में बिहार पवेलियन के माध्यम से फिल्म निर्माताओं के साथ ही फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024, राज्य के शूटिंग लोकेशन, बिहार पोर्टल रजिस्ट्रेशन, फिल्म निगम के अन्य क्रियाकलाप आदि की जानकारी दी जाएगी एवं राज्य में फिल्म उद्योग को विकसित करने को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। इस दौरान निगम के प्रतिनिधि यहां भाग ले रहे अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों से फिल्म उद्योग से जुड़े नवाचारों को समझेंगे। आईएफएफआई के इस संस्करण में फिल्म निगम की ओर से 23 नवम्बर को शाम 4:30 बजे से 'पॉलिसी टू पिक्चर: बिहार सिनेमैटिक राइज' विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया जाना है। इस सत्र में हिंदी फिल्म रजनी की बारात की निर्माता तनाया अदरकर प्रभु और हिंदी फिल्म टिया के निर्माता सागर श्रीवास्तव बिहार में फिल्म शूटिंग से जुड़े अपने अनुभव फिल्म कम्युनिटी से साझा करेंगे। फिल्म रजनी की बारात की शूटिंग मुख्य रूप से दरभंगा में हुई है जबकि टिया की शूटिंग वाल्मीकि नगर सहित राज्य के कई जिलों में हुई है।

बिहार को बदहाली और अपराध के दौर से निकालकर विकास की राह पर लाने में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान : संजय सरावगी

पटना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बने पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखे जाने को पूरी तरह उचित और वाजिब निर्णय बताया। नीतीश कुमार बिहार के विकास के सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने अपने सुशासन के माध्यम से बिहार में बदलाव की नई इबारत लिखी है। बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। संजय सरावगी ने कहा कि जो लोग नीतीश सेतु के नामकरण का विरोध कर रहे हैं, वे सही मायने में नीतीश कुमार से नफरत करते हैं। नीतीश कुमार से नफरत करने वाले राजद को बिहार की जनता पहले ही राजनीतिक रूप से पूरी तरह हाशिये पर डाल चुकी है और आगे भी राजद जो नफरत दिखा रही है और आगे भी जनता उसे हाशिये पर डालेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास और सुशासन को महत्व देती है तथा राज्य के विकास में योगदान देने वाले नेताओं का सम्मान करना जानती है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक समय बिहार बदहाली, अपराध और अराजकता के दौर से गुजर रहा था। राज्य को विकास से वंचित रखने वाले लोगों ने बिहार की छवि को देशभर में खराब किया था। ऐसे दौर से बिहार को निकालकर नीतीश कुमार ने सुशासन और विकास की राह पर आगे बढ़ाया। उनके शासनकाल में बिहार में बदलाव आया और विकास की नई संभावनाएं बनीं। सड़क, पुल, बिजली और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुए बदलाव ने राज्य की प्रगति को नई गति दी और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। उन्होंने कहा, 'विडंबना है कि जिन लोगों ने बिहार को अंधकार में रखा, वे आज नीतीश कुमार के नाम पर बने सेतु का विरोध कर रहे हैं। दरअसल, उनका विरोध केवल नीतीश कुमार से नहीं, बल्कि बिहार के विकास और राज्य की बदली हुई पहचान से भी है। संजय सरावगी ने कहा कि प्रदेश के विकास में नीतीश कुमार के योगदान को बिहार की जनता कभी भुला नहीं सकती। नीतीश सेतु उनके विकास संबंधी योगदान और बिहार में सुशासन के दौर की एक महत्वपूर्ण पहचान है। ऐसे में इस नामकरण पर सवाल उठाना राज्य के विकास में उनके योगदान को नकारने जैसा है।

सुपौल में राज्यस्तरीय अंतर प्रमंडल विद्यालय बालिका खेल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ

सुपौल,एजेंसी। जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और बालिका खिलाड़ियों को राज्यस्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुवार को सुपौल टाउन हॉल में राज्यस्तरीय अंतर प्रमंडल विद्यालय बालिका खेल प्रतियोगिता 2026-27 का भव्य शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी सावन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर तीन दिवसीय प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न प्रमंडलों से पहुंची अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 आयु वर्ग की बालिका खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। इस राज्यस्तरीय आयोजन में कुल 321 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इनमें विभिन्न प्रमंडलों से आई 297 बालिका खिलाड़ी, नौ दल प्रभारी तथा 15 तकनीकी पदाधिकारी शामिल हैं। 19 से 21 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

उद्घाटन समारोह में उप विकास आयुक्त हरिहर प्रसाद, अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन, वरीय उप समाहर्ता पुष्पा कुमारी, वरीय उप समाहर्ता अंजू कुमारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी तथा जिला कला, संस्कृति एवं युवा पदाधिकारी तारकेश्वर प्रसाद सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सावन कुमार ने कहा कि खेल के क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है



खिलाड़ियों को उचित मंच, संसाधन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की। इस तरह की प्रतियोगिताएं बालिका खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली चयनित खिलाड़ियों को आगे राज्य एवं अन्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हार-जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन अनुशासन, मेहनत, समर्पण और खेल भावना ही एक अच्छे खिलाड़ी की असली पहचान होती है। सभी खिलाड़ी पूरे उत्साह और लगन के साथ प्रतियोगिता में भाग लें तथा अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करें। विभिन्न प्रमंडलों से पहुंची खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से आवासन एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के साथ उनके ठहरने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए दल प्रभारियों एवं तकनीकी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित की गई हैं।19, 20 एवं 21 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में तीन आयु वर्गों की खिलाड़ी अपनी मेहनत, कौशल और खेल क्षमता का प्रदर्शन करेंगी। राज्य के विभिन्न प्रमंडलों से बालिका खिलाड़ियों की भागीदारी से आयोजन को विशेष महत्व मिला है। प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने के साथ आगे की खेल प्रतियोगिताओं में जगह बनाने का अवसर भी मिलेगा।

बेतिया में सेनको एन्ड डायमंड शोरूम मे हुई लूट का पुलिस को मिला सुराग

बेतिया,हि.स.। बेतिया शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग एनएच-727 के किनारे स्थित सेनको एन्ड डायमंड शोरूम मे बुधवार की दोपहर अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देकर बाइक से फरारा हो गए।इस लूट की घटना से शहर ही नही बल्कि जिले मे संसनी फैल गई।घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंच कर छानबीन मे लग गई।अपराधियों द्वारा शोरूम से लगभग 15 कडोड की लूट की है। सोशल मीडिया पर शोरूम के सीनियर एक्सीयूटिव कैसियर मोहित कुमार ने बताया कि आठ की संख्या मे अपराधी थे।सभी के हाथो मे हथियार थे।एक अपराधी हथियार के बल पर गार्ड को कब्जे मे लेकर बाहर नजर रखे हुआ था।उसके तीन अपराधी हथियार के साथ अंदर प्रवेश किया।उसके लगभग तीन मिनट के बाद बाकी अपराधी अंदर प्रवेश किए।उन्होंने बताया की दुकान के अंदर जब हलचल सुनाई दी तो दूसरे तल्ले से उतरा तबतक अपराधियों ने गण पॉइंट पर ले लिया।

उन्होने बताया कि एक अपराधी सभी कर्मियों व ग्राहकों का मोबाईल लेकर एक रूम मे बंद कर दिया।दूसरा अपराधी गन पॉइंट पर ले लिया,जबकि पांच अपराधी सोने व डायमंड् के गहनो को बैग मे भर रहा था।अपराधियों ने शो रूम से लगभग 15 कड़ोड की लूट की है। इस घटना के बाद से व्यवसाइयो दहशत का माहौल है।



इस हाई-प्रोफाइल वारदात के उद्भेदन के लिए एसएसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी (विशेष जांच टीम) और पटना मुख्यालय से आई एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की टीम ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाल लिया है।पुलिस के द्वारा चार संदिग्धो को हिरासत मे लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में इस पूरी वारदात के तार समस्तीपुर और वैशाली जिले के कुख्यात अंतरजिला लुटेरा गिरोह से जुड़ते नजर आ रहे हैं।अपराधियों के द्वारा लगभग 30 फीसदी की लूट की आसंका जताई जा रही है।लूट के बाद दुकान मे घने गिरे हुए थे।अभी बिल के द्वारा आभूषणों का आकलन किया जा रहा है। वारदात के तुरंत बाद हरकत में आई पुलिस ने मौके पर डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम को बुलाया था। एफएसएल की टीम द्वारा बारीकी से साक्ष्य को इकट्ठा किया गया।पुलिस के द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए डॉग स्क्वायड की टीम को बुलाया गया।डॉग स्क्वायड की निशानदेही पर पुलिस को अपराधियों के भागने के रूट और उनके ठिकानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं।इसके साथ ही शोरूम के आस पास व शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस ने लूटकांड में प्रयुक्त बाइकों की पहचान कर ली है। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित विशेष टीम इन सुरागों के आधार पर जिले के विभिन्न संदिग्ध ठिकानों के साथ-साथ बाहरी जिलों में भी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।

युवाओं की आत्मनिर्भरता से ही समाज की वास्तविक प्रगति संभव : युवराज कपिलेश्वर सिंह

दरभंगा। युवाओं का शिक्षित होने के साथ आत्मनिर्भर बनना भी जरूरी है। समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब युवा अपने हुनर और क्षमता के बल पर रोजगार हासिल कर आत्मनिर्भर बनें। ये बातें राज दरभंगा के युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह ने अम्बेडकर युवा केन्द्र की ओर से आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। अम्बेडकर मॉडल स्कूल परिसर में अम्बेडकर युवा केन्द्र एवं 'डॉक्टर्स फॉर यू' की सीएसआर पहल के तहत संचालित गरिमा प्रोजेक्ट के तत्वावधान में आयोजित समारोह में व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवक-युवतियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक के रूप में उपस्थित युवराज कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि अम्बेडकर युवा केन्द्र से जुड़ना उनके लिए महज एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज सेवा का पवित्र संकल्प है। उन्होंने संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर और अपने दादाजी महाराज कामेश्वर सिंह के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों विभूतियों ने स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बाबासाहेब के मूल मंत्र 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि शिक्षा के साथ कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। युवराज ने वर्ष 2009 में स्थापित अम्बेडकर युवा केन्द्र की 17 वर्षों की सामाजिक यात्रा की सराहना करते हुए



कहा कि संस्था ने वंचित और गरीब वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया है। गरिमा प्रोजेक्ट के माध्यम से युवक-युवतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना सराहनीय पहल है। उन्होंने संस्था के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। इस अवसर पर उन्होंने राजा सल्हेश मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण में भी सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही विजय कुमार पासवान एवं उनकी पूरी टीम को सफल आयोजन और सामाजिक कार्यों के लिए बधाई दी। समारोह में राज दरभंगा के प्रबंधक आशुतोष दत्ता, अमरकांत झा, सीएम सिंह, आशीष झा, सत्यम सिंह, दीपक कुमार, बबलू कुमार, संतोष सिंह, राजू मंडल, प्रभाकर, मुकेश सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

एक नजर

प्रयागराज : 41वीं इंदिरा मैराथन में सेना के धावक प्रदीप चौधरी ने मारी बाजी, महिला वर्ग में यूपी पुलिस की नीतू प्रथम

प्रयागराज,एजेंसी। संगम नगरी में आयोजित 41वीं इंदिरा मैराथन में देशभर से आए धावकों ने अपनी दमखम, धैर्य और खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। 42 किलोमीटर की इस प्रतिष्ठित मैराथन के पुरुष वर्ग में सेना में नायब सूबेदार प्रदीप चौधरी ने लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान हासिल कर अपनी श्रेष्ठता साबित की। वहीं महिला वर्ग में नीतू सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। इस खबर का अपडेट बाद में किया जाएगा। पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता में प्रदीप चौधरी ने निर्धारित दूरी सबसे पहले पूरी कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। मुंबई के राज तिवारी ने द्वितीय और उत्तराखंड के निखिल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में नीतू सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया। यूपी पुलिस की नीतू ने महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। नीतू प्रयागराज की रहने वाली हैं। वह मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में ही अभ्यास करती हैं संध्या यादव दूसरे स्थान पर रहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही अन्नू ने तीसरा स्थान हासिल कर पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया। मैराथन में शामिल धावकों ने पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ दौड़ पूरी की। प्रतियोगिता ने एक बार फिर प्रयागराज की खेल परंपरा और एथलेटिक्स के प्रति लोगों के उत्साह को प्रदर्शित किया। बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने भी धावकों का उत्साहवर्धन किया। 41वीं इंदिरा मैराथन के आयोजन ने शहर में खेल गतिविधियों को नई ऊर्जा दी। हालांकि, आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। भविष्य में इस प्रतिष्ठित आयोजन को और बेहतर बनाने के लिए यातायात प्रबंधन तथा धावकों की सुविधा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहली बार हाफ इंदिरा मैराथन 21 किलोमीटर की मैराथन में धावको का काफी उत्साह दिखाई है। धावको की संख्या में वृद्धि हुई है।

आईएसपीएल सीजन-4 के लिए बेंगलुरु स्ट्राइकर्स तैयार, ऋतिक रोशन को टीम से खिताब जीतने की उम्मीद

नई दिल्ली। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) के चौथे सीजन के लिए बेंगलुरु स्ट्राइकर्स तैयार है। टीम के मालिक ऋतिक रोशन ने अपने खिलाड़ियों को बेहतरीन बताते हुए भरोसा जताया कि इस बार बेंगलुरु स्ट्राइकर्स के पास खिताब जीतने का मजबूत मौका है। बेंगलुरु स्ट्राइकर्स ने खिलाड़ियों की नीलामी के बाद 18 सदस्यीय नई टीम तैयार की है। टीम ने सभी विभागों में मजबूती लाने पर ध्यान दिया है, जिसमें योगेश पेनकर और सुमीत ढेकाले जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा टीम में गौरेश नागवेकर, फिरोज शेख, जैद खान, जिग्नेश पटेल और मयूर वाघमारे जैसे खिलाड़ी भी हैं। नई टीम में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन के अच्छे विकल्प मौजूद हैं। पिछले सीजन में शीर्ष पांच टीमों में जगह बनाने वाली बेंगलुरु स्ट्राइकर्स इस बार अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहेगी। टीम का लक्ष्य खिताब की मजबूत दावेदारी पेश करना होगा। आगामी सीजन की तैयारियों और टीम से उम्मीदों पर ऋतिक रोशन ने एक बयान में कहा कि ‘मैं नए सीजन और इस टीम की संभावनाओं को लेकर बेहद उत्साहित हूं। हमारे साथ कुछ शानदार खिलाड़ी जुड़े हैं और मुझे लगता है कि हमारे पास एक बेहतरीन टीम है। बेंगलुरु स्ट्राइकर्स से जुड़े सभी लोग शुरुआत करने के लिए उत्सुक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारे पास खिताब जीतने का मजबूत मौका है। उभरते खिलाड़ियों को मंच देने में आईएसपीएल की भूमिका पर बात करते हुए अभिनेता ने कहा कि ‘मेरे लिए आईएसपीएल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करती है, जिन्हें शायद कहीं और ऐसा मौका न मिल पाता। हमारे देश में बहुत प्रतिभा है और मुझे लगता है कि आईएसपीएल जैसी लीग उन प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस लीग से निकले खिलाड़ी आगे चलकर बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे और भारतीय क्रिकेट में बड़े स्तर पर योगदान देंगे। आईएसपीएल का चौथा सीजन गोवा में आयोजित हो रहा है। लीग का लक्ष्य पिछले सीजन से मिल रहे उत्साह को आगे बढ़ाने के साथ उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक और बड़ा अवसर देना है।

'फैब फोर' का हिस्सा होने का कभी दबाव महसूस नहीं किया : विलियमसन

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने क्रिकेट के मशहूर 'फैब फोर' का हिस्सा होने को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी इस प्रतिष्ठित समूह में शामिल होने का अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं हुआ। उनके लिए हमेशा टीम की जीत और देश के लिए उपयोगी योगदान देना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। दरअसल 'फैब फोर' शब्द न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्टिन क्रो ने 2014 में विलियमसन, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट के लिए कहा था। उनका मानना था कि ये खिलाड़ी आगे चलकर अपने देशों को लीड करेंगे और आने वाले वर्षों में बहुत सारे रन बनाएंगे। इन सभी खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए ढेरों रन बनाए और महान क्रिकेटरों में एक बने। खासकर विराट ने 28,000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन और 86 शतक के साथ, सभी फॉर्मेट के महान खिलाड़ी के तौर पर एक मजबूत पहचान बनाई है। विलियमसन ने आईसीसी रिव्यू के हालिया एपिसोड में पूर्व इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन से बातचीत के दौरान 'फैब फोर' में अपनी जगह और अपने अनुभवों पर खुलकर चर्चा की। पूर्व दिग्गज ने कहा कि उन्हें कभी फैब फोर का हिस्सा होने का दबाव महसूस नहीं हुआ। उन्होंने विराट कोहली, जो रूट और स्टीव स्मिथ की जमकर तारीफ की। विलियमसन के मुताबिक, वह इन तीनों खिलाड़ियों का काफी सम्मान करते हैं और उनके खेलने के अंदाज को पसंद करते हैं।

उन्होंने कहा कि मुझे कभी इसका बोझ महसूस नहीं हुआ। मैं फैब फोर के बाकी तीनों खिलाड़ियों की बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। जो रूट के साथ यॉर्कशायर में खेल चुका हूं और बाकी खिलाड़ियों के खिलाफ लंबे समय तक क्रिकेट खेला है। मैं उनके खेलने के तरीके का बहुत सम्मान करता हूं। ये तीनों खिलाड़ी एक-दूसरे से काफी अलग हैं। विलियमसन ने कहा कि व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करना और फैब फोर के अन्य खिलाड़ियों के साथ अपना नाम जुड़ना निश्चित रूप से खास था, लेकिन उनका ध्यान हमेशा न्यूजीलैंड टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करने पर रहा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य टीम के लिए लगातार उपयोगी योगदान देना और अपने खेल में सुधार करते रहना था। अलग-अलग परिस्थितियों और समय में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तुलना करना आसान नहीं होता। इसलिए उन्होंने कभी इस तुलना को ज्यादा महत्व नहीं दिया। विलियमसन ने यह भी कहा कि संन्यास के बाद जब वह अपने करियर को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें यह काफी खास लगता है कि चारों खिलाड़ी लंबे समय तक एक साथ टेस्ट क्रिकेट में सक्रिय रहे और उन्होंने खूब रन बनाए। बातचीत के दौरान विलियमसन से यह भी पूछा गया कि मौजूदा क्रिकेट में कौन से युवा बल्लेबाज भविष्य में फैब फोर जैसा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस पर विलियमसन ने पांच खिलाड़ियों के नाम बताए। उनकी सूची में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, भारत के शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन और न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र शामिल हैं।

भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट: पहले दिन किवी बल्लेबाजों ने 5 विकेट पर बनाए 243 रन, निकोल्स का शतक

वेलिंग्टन,एजेंसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंग्टन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है। दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में पांच विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए हैं। स्टंप्स के समय हेनरी निकोल्स 221 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 113 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ग्लेन फिलिप्स 182 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अब तक तीन विकेट झटके हैं। वहीं, अंशुल कंबोज और आकाशदीप को एक-एक सफलता मिली है।



इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती झटके देते हुए 70 रन के स्कोर तक मेजबान टीम के पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद डेवोन कॉनवे 4 रन, रचिन रवींद्र 15 रन, डेरिल मिचेल एक रन और टॉम ब्लंडेल 5 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय गेंदबाजों की दमदार शुरुआत को देखते हुए लग रहा था कि न्यूजीलैंड की पहली पारी जल्द सिमट जाएगी। हालांकि, इसके बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने संयम और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया और अटूट साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 240 के पार पहुंचाया। इस दौरान निकोल्स ने अपना शतक भी पूरा किया, जबकि फिलिप्स अपने शतक से महज छह रन दूर हैं। निकोल्स को पारी के दौरान एक जीवनदान भी मिला।

जब वह 102 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब देवदत्त पडिक्कल ने उनका आसान कैच छोड़ दिया। भारतीय टीम को इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा और निकोल्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। फिलहाल पहले दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने पांच विकेट पर 243 रन बना लिए हैं। निकोल्स 113 और फिलिप्स 94 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की कोशिश इस साझेदारी को जल्द तोड़कर न्यूजीलैंड की पारी को समेटने की होगी।

'सिराज विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं', प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने पर कोटक ने दी सफाई

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को नहीं खिलाने के फैसले का भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बचाव किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिराज एक 'विश्वस्तरीय गेंदबाज' हैं लेकिन टीम प्रबंधन का मानना था कि इस मुकाबले के लिए चुनी गई प्लेइंग इलेवन सबसे बेहतर संयोजन है।

भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में चार तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और अंशुल कंबोज के साथ उतरी, जबकि सिराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ा। इस फैसले ने क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा शुरू कर दी। क्रिकबज के मुताबिक वेलिंगटन में पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सितांशु कोटक ने सिराज को बाहर रखने के फैसले पर अपनी बात रखी। कोटक ने कहा कि सिराज के साथ कुछ भी गलत नहीं है। मेरा मतलब है कि मुझे कोई समस्या नजर नहीं आती। टीम प्रबंधन को लगा कि यही सबसे अच्छी प्लेइंग इलेवन है और इसी टीम के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया गया। कोटक ने श्रीलंका दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की परिस्थितियां न्यूजीलैंड से अलग थीं। श्रीलंका में सिराज ने दोनों टेस्ट मैच खेले थे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सिराज एक विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने मैदान पर जो गेंदबाजी आक्रमण उतारा, उसमें काफी विविधता थी। कोटक ने कहा कि दो गेंदबाज सीम (सीम मूवमेंट) कराने में माहिर हैं तो दो स्विंग कराने में और जाहिर है गति भी मायने रखती है। जब आप ऐसी पिच पर खेल रहे हों जो थोड़ी नम हो, शुरुआत में नरम हो और जिस पर काफी घास हो तो एक लंबा गेंदबाज होना फायदेमंद होता है क्योंकि इससे अतिरिक्त उछाल मिलता है। उन्होंने कहा कि यह तो बस पहला दिन है, जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच पर कुछ निशान या गड्ढे बनेंगे। इसलिए, जब आप अपनी प्लेइंग इलेवन चुनते हैं, तो आप पूरे चार या पांच दिनों के बारे में सोचते हैं। सिराज को टीम में न रखना एकमात्र ऐसा फैसला नहीं था जिस पर सवाल उठे। भारतीय टीम ने स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर रवींद्र जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता दी। कोटक ने इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि न्यूजीलैंड की टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की संख्या ज्यादा थी।

मप्र के भोपाल में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज, चीन और थाईलैंड के बीच उद्घाटन मैच शुरु

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का रोमांच शुरू हो गया है। उद्घाटन मुकाबले में चीन ने थाईलैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे क्वार्टर तक पांच गोल दाग दिए। 19 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत समेत छह देशों की टीमें खिताब के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। दरअसल, भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 की शुरूआत हो चुकी है। प्रतियोगिता के पहले दिन मेजबान भारतीय महिला हॉकी टीम अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया के विरुद्ध करेगी।

भारत और मलेशिया के बीच मुकाबला शाम 4:35 बजे खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सहित चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की छह टीमें हिस्सा लेंगी। सभी टीमें भोपाल पहुंच चुकी हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन तीन मुकाबले खेले जाएंगे। चीन और थाईलैंड के बीच उद्घाटन मैच शुरू हो गया है। इसके बाद जापान और कोरिया की टीमें आमने-सामने होंगी। मेजबान भारतीय टीम शाम 4:45 बजे मलेशिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इसके बाद शाम 6:30 बजे औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा।

भोपाल में इससे पहले वर्ष 2009 में वर्ल्ड सीरीज हॉकी का आयोजन हो चुका है। ऐशबाग स्टेडियम में कई वर्षों तक पुरुष हॉकी के राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले भी खेले गए हैं, लेकिन महिला हॉकी का अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट पहली बार राजधानी में आयोजित हो रहा है। टूर्नामेंट में शामिल टीमों की विश्व रैंकिंग पर नजर डालें तो चीन चौथे स्थान के साथ सबसे मजबूत टीम है। भारतीय टीम सातवें स्थान पर है। जापान 11वें, कोरिया 15वें, मलेशिया 21वें और थाईलैंड 28वें स्थान पर है। एशियाई रैंकिंग में चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पर है। ऐसे में भारतीय टीम के सामने घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन कर खिताब की दावेदारी मजबूत करने की चुनौती होगी। भारतीय टीम लीग चरण में सभी पांच प्रतिद्वंद्वी देशों से मुकाबला करेगी। उसका पहला मैच 19 नवंबर को मलेशिया के खिलाफ होगा। इसके बाद 21 नवंबर को कोरिया, 22 नवंबर को थाईलैंड, 24 नवंबर को चीन और 25 नवंबर को जापान से सामना होगा।

सविता को 'टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया' की सूची में मिली जगह, हॉकी इंडिया ने दी बधाई

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज गोलकीपर और पद्मश्री से अलंकृत सविता का नाम पहली बार जारी 'टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया' (TIME100 Next: India) लिस्ट में शामिल किया गया है। इस सूची में उन 100 प्रभावशाली हस्तियों को जगह दी गई है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में अपने योगदान, नेतृत्व और प्रभाव से भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं। सविता को इस सम्मान पर हॉकी इंडिया ने उन्हें बधाई दी।

भारतीय गोलकीपर को इस सूची की 'लीडर्स' श्रेणी में शामिल किया गया है। यह भारतीय हॉकी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि खेल के क्षेत्र में उनके योगदान और नेतृत्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया की पहली सूची में सविता को कई अन्य चर्चित भारतीय हस्तियों के साथ शामिल किया गया है। इनमें अभिनेता दिलजीत दोसांझ, विक्की कौशल, अभिनेत्री आलिया भट्ट, भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू, शतरंज खिलाड़ी डी. गुकेश और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां शामिल हैं। इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए सविता ने कहा कि टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया की पहली सूची में जगह मिलना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। मैं उन प्रेरणादायक लोगों के बीच शामिल होकर खुद



को गौरवान्वित और विनम्र महसूस कर रही हूं, जो अलग-अलग तरीकों से भारत के भविष्य में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बल्कि भारतीय हॉकी, मेरी साथी खिलाड़ियों, कोचों और उन सभी लोगों का है, जिन्होंने मेरे पूरे सफर में मेरा साथ दिया है। मुझे उम्मीद है कि इससे अधिक से अधिक युवा लड़कियां खेलों को अपनाने, बड़े सपने देखने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित होंगी कि वे भी बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकती हैं।'

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप टिर्की ने सविता को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया की सूची में सविता को जगह मिलना भारतीय हॉकी के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने अपने पूरे करियर में असाधारण प्रतिबद्धता, संघर्ष क्षमता और नेतृत्व का परिचय देते हुए हमारे खेल की बेहतरीन प्रतिनिधि के रूप में पहचान बनाई है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा कि यह सविता और भारतीय हॉकी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्षों से उनके समर्पण, निरंतरता और शानदार प्रदर्शन ने उन्हें इस खेल की सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में शामिल किया है। टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया जैसी प्रतिष्ठित पहल में जगह मिलना यह दर्शाता है कि खिलाड़ी अपनी खेल उपलब्धियों से आगे बढ़कर भी समाज को प्रभावित कर सकते हैं। हम सविता को बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया की सम्मानित हस्ती के रूप में सविता को 12 दिसंबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित होने वाले टाइम 100 नेक्स्ट गाला (ञ्ज्ञद्बह्लख्श100 ह्वद्म×ह्ल ल्लड्डद्यड्ड) में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। टाइम 100 नेक्स्ट पहल दुनियाभर में उभरते नेताओं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले प्रभावशाली लोगों को पहचान देने के लिए विश्व स्तर पर जानी जाती है। इसे पहली बार विशेष रूप से भारत के लिए पेश किया गया है। इसे रिलायंस का समर्थन प्राप्त है और यह देश के विभिन्न क्षेत्रों से असाधारण प्रतिभाओं और बदलाव लाने वालों को एक मंच पर लाती है।

वाराणसी में 29 नवंबर से नौ दिसंबर तक होगी राष्ट्रीय शतरंज चैम्पियनशिप, विजेताओं को मिलेंगे तीस लाख रुपए के पुरस्कार

वाराणसी,एजेंसी। उत्तर प्रदेश शतरंज खेल संघ के सचिव ए. के. रायजादा व आयोजन समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज ने आज वाराणसी में रामकटोरा स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि 63 वीं सेठ एम आर जैपुरिया राष्ट्रीय शतरंज चैम्पियनशिप 2026 का आयोजन 29 नवंबर से नौ दिसंबर 2026 तक वाराणसी के सेठ एम. आर. जैपुरिया स्कूल्स बनारस के बाबतपुर कैंपस में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन एवं वाराणसी शतरंज संघ के संयुक्त सहयोग से, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के तत्वावधान में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य देशभर के प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। इसमें विजेताओं को इनाम में तीस लाख रुपए की धनराशि मिलेगी।

पत्रकार वार्ता में ए. के. रायजादा व दीपक कुमार बजाज ने आगे बताया कि यह ग्यारह दिवसीय विशाल आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहली बार किया जा रहा है। इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथियों व खेल प्रेमियों का भी आगमन होगा। इस प्रतियोगिता में 33 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों व संस्थागत इकाइयों के विजेता एवं खुले प्रवेश के माध्यम से कुल 500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इस अवसर पर



22 ग्रैण्ड मास्टर 30 इण्टरनेशनल मास्टर एवं 50 से अधिक अन्य खिताबधारी खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी विभिन्न विश्व स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय शतरंज दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज ने बताया कि यह 63 वीं सेठ एम. आर. जैपुरिया राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, वाराणसी 2026 का मैत्रीपूर्ण चेहरा और काशी के गौरवशाली प्रतिनिधि के रुप में प्रतिबिम्बित है। प्रतियोगिता में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ट्राफी, मेडल, प्रमाण पत्र के साथ साथ पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएंगी। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को छह लाख, द्वितीय स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को पांच लाख तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को चार लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी इसी तरह चौथे स्थान के लिए 3 लाख, पाँचवें एवं छठे स्थान के लिए 2.50 लाख प्रत्येक, सातवें एवं आठवें स्थान के लिए 2 लाख प्रत्येक तथा नौवें एवं दसवें स्थान के लिए 1.50 लाख से सम्मानित किया जाएगा। इस खेल में 11 राउंड में मुकाबला होगा। कार्यक्रम के कुशल संयोजन हेतु नगर के गणमान्य व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से युक्त एक संरक्षक मण्डल बनाया गया है। इस आयोजन के संरक्षकों में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल, राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु, वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी, मंडलायुक्त एम. राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर. के. चौधरी व सेठ एम.आर. जैपुरिया स्कूल्स समूह के उपाध्यक्ष श्रीवत्स जैपुरिया शामिल हैं। इन प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन से राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता को विशेष गरिमा और प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत में गोल्फ सुविधा विकसित करने को पीजीए ऑफ अमेरिका और विमत्रा वेंचर्स की साझेदारी

फ्रिस्को। अमेरिका की प्रमुख गोल्फ संस्था पीजीए ऑफ अमेरिका ने भारत में गोल्फ के विकास को नई गति देने के लिए सैन फ्रांसिस्को स्थित वेंचर कैपिटल फर्म विमत्रा वेंचर्स के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत भारत में पीजीए ब्रांडेड गोल्फ कम्युनिटी विकसित की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना में आधुनिक गोल्फ सुविधा और आवासीय कम्युनिटी का विकास किया जाएगा। यहां रहने वाले लोगों और आगंतुकों को पीजीए से प्रेरित गोल्फ कार्यक्रमों, कोचिंग, खिलाड़ियों के विकास से जुड़ी पहल और प्रीमियम गोल्फ सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस परियोजना की पहली सुविधा वर्ष 2029 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुरू करने की योजना है। यह साझेदारी भारतीय गोल्फ में विमत्रा वेंचर्स के निवेश को भी आगे बढ़ाएगी। कंपनी हाल ही में स्थापित एएम ग्रीन इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) में चेन्नई लायंस जीसी फ्रेंचाइजी की मालिक है। इस टीम ने अनुभवी भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर के नेतृत्व में हैदराबाद और विशाखापत्तनम में लगातार दो आईजीपीएल खिताब जीते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य केवल गोल्फ कोर्स विकसित करना नहीं बल्कि गोल्फ को केंद्र में रखकर ऐसा आवासीय और मनोरंजक वातावरण तैयार करना है, जहां लोग खेल से जुड़ सकें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकें।

पीजीए ऑफ अमेरिका के ग्लोबल डेवलपमेंट निदेशक सीन थॉर्नबेरी ने कहा कि भारत, वैश्विक स्तर पर गोल्फ के विकास के लिए बेहतरीन दीर्घकालिक अवसर पेश करता है। विमत्रा वेंचर्स के साथ साझेदारी से हमें पीजीए ऑफ अमेरिका के ब्रांड की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को ऐसे संगठन की विशेषज्ञता के साथ जोड़ने का अवसर मिलेगा, जो भारत के निवेश परिदृश्य और गोल्फ बाजार को अच्छी तरह समझता है। हम इस नई परियोजना को लेकर उत्साहित हैं। इसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को गोल्फ से जोड़ने के साथ भारत में गोल्फ आधारित आवासीय जीवनशैली के लिए एक नया मानक स्थापित करने की दिशा में काम किया जाएगा। विमत्रा वेंचर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष यम्माडा ने कहा कि भारत में गोल्फ एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसके पीछे उपभोक्ताओं की बढ़ती रुचि, निवेश में विस्तार और प्रीमियम लाइफ स्टाइल अनुभवों की बढ़ती मांग है। उन्होंने कहा कि पीजीए ऑफ अमेरिका के साथ साझेदारी से हमें गोल्फ के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों में से एक को भारत लाने का मौका मिला है।

एक नजर

कीव पर रूसी ड्रोन हमले में ऑस्ट्रियाई दूतावास की इमारत को नुकसान

कीव,एजेंसी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ताजा ड्रोन हमलों के दौरान ऑस्ट्रियाई दूतावास की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीएटे माइनल-राइजिंगर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दूतावास के बाहर एक विस्फोटक वस्तु आकर गिरी, जिससे इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बताया कि मध्य कीव स्थित ऑस्ट्रियाई दूतावास के ठीक बाहर दोपहर में एक प्रक्षेप्य गिरा। उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां तैनात कर्मचारियों से फोन पर बात की है और सभी के सुरक्षित होने की जानकारी मिलने से उन्हें राहत मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। माइनल-राइजिंगर ने कहा कि कीव पर रूस के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कठिन और खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद काम कर रहे दूतावास के पूरे दल के प्रति आभार जताया और उनके समर्पण की सराहना की।

क्रीमिया पुल पर हमले के बाद पुतिन ने काला सागर और ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की संभावना खारिज की

मॉस्को। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर यूक्रेन के हमलों के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर और ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने के किसी भी समझौते की संभावना खारिज कर दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस इन हमलों का जवाब देगा और उसकी कार्रवाई यूक्रेन के हमले से कहीं अधिक कड़ा प्रहार होगी। पुतिन ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन ने एक सप्ताह के भीतर तीसरी बार क्रीमिया पुल को निशाना बनाया है। यह हमला ऐसे समय हुआ, जब चीन के शेनझेन में एपीईसी शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन ने चीन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की थी। वार्ता के बाद पुतिन ने बताया कि उन्होंने रूस की सुरक्षा परिषद के साथ समुद्र और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के संभावित समझौते पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से इस प्रस्ताव पर और विचार करने तथा बाद में अपनी राय देने को कहा गया था। उन्हें उम्मीद थी कि इस दिशा में कोई सहमति बन सकती है। हालांकि, क्रीमिया पुल पर हमले के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि अब ऐसा कोई समझौता नहीं होगा। पुतिन ने कहा, 'हम इन हमलों का जवाब देंगे। मैं चाहता हूं कि सभी यह जान लें कि हमारी प्रतिक्रिया की चोट कीव शासन की ओर से पुल पर किए गए हमले से कहीं अधिक गंभीर होगी। रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि क्रीमिया पुल का इस्तेमाल केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उन्होंने यूक्रेन के उस आरोप को खारिज किया कि इस पुल से सैन्य उपकरण या पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई होती है। पुतिन ने कहा कि रूस पुल को दोबारा बनाने का काम करेगा। उनके अनुसार, पुल के सड़क वाले हिस्से को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

नाइजीरिया में आत्महत्या के प्रयास को अपराधमुक्त करने की तैयारी, राष्ट्रपति ने संसद से मांगी मंजूरी

अबुजा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टीनुबू ने आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों को अपराधी मानने के बजाय उन्हें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के रूप में देखने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संसद से कानून में बदलाव करने का आग्रह किया है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और इससे गुजर चुके लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, गुरुवार को सामने आए विधेयक के साथ भेजे गए पत्र में राष्ट्रपति टीनुबू ने कहा कि प्रस्तावित बदलावों के जरिए आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा और प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल नाइजीरिया की आपराधिक और दंड संहिताओं के तहत आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को जुर्माना, एक साल तक की कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं। संसद से विधेयक पारित होने पर इस व्यवस्था में बदलाव होगा और दंडात्मक कार्रवाई के स्थान पर देखभाल तथा पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रस्तावित कानून के तहत संबंधित अधिकारियों को आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों के लिए पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर पहुंचा काठमांडू, लाहौर अव्वल तो ढाका दूसरे स्थान पर



काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था आईक्यूएयर (ङ्ढन्नह्वह्व) के अनुसार, गुरुवार सुबह 9 से 10 बजे के बीच काठमांडू 181 एयर क्वालिटी इंडेक्स (ऌह्ह्व) के साथ दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में तीसरे स्थान पर रहा। इस दौरान पाकिस्तान का लाहौर 327ऌह्ह्व के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका 227ऌह्ह्व के साथ दूसरे स्थान पर थी। सर्दियों की शुरुआत के साथ काठमांडू की वायु गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है। बारिश में कमी, वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर उड़ती धूल और निर्माण गतिविधियों को वायु प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण माना जा रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण काठमांडू घाटी का आसमान धुंधला होने लगा है। इसका असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बढ़ता वायु प्रदूषण अधिक खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के तहत लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने और बाहर जाते समय मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

शी जिनपिंग ने एपेक सम्मेलन में एशिया-प्रशांत के विकास के लिए पेश किया चार सूत्रीय विजन

शेनझेन,एजेंसी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 33वीं एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) आर्थिक नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए एशिया-प्रशांत समुदाय के निर्माण के लिए चार प्रमुख दृष्टिकोण पेश किए। उन्होंने एकजुटता एवं आपसी सहयोग, खुलेपन एवं आर्थिक एकीकरण, उद्यमशीलता एवं नवाचार तथा समावेशी विकास को क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य का आधार बताया। जिनपिंग ने कहा कि चीन सभी देशों के साथ मिलकर ऐसा एशिया-प्रशांत समुदाय बनाना चाहता है, जहां साझा विकास और आपसी सहयोग को प्राथमिकता मिले।

भारत में चीनी राजदूत शू फेईहोंग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स लिखा, शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया इस समय बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। विज्ञान, तकनीक और उद्योगों में तेजी से हो रहे नवाचार के बीच एशिया-प्रशांत देशों को नई परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना होगा। एपेक की शुरुआत के बाद पिछले तीन दशकों में क्षेत्र ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और अब इस उपलब्धि को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने सदस्य देशों से खुले व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, आर्थिक एकीकरण मजबूत करने तथा व्यापारिक बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया। साथ ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार को क्षेत्रीय विकास का प्रमुख आधार बताया। चीनी राष्ट्रपति ने एशिया-प्रशांत सहयोग के चार प्रमुख स्तंभ भी सामने रखे। इनमें व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, नवाचार और सतत विकास शामिल



हैं। उन्होंने एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीएएपी) के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, सीमा पार भुगतान को आसान बनाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर रखने पर जोर दिया।

जिनपिंग ने ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास, रोजगार सृजन तथा कौशल विकास में सहयोग बढ़ाने की जरूरत भी बताई। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और युवाओं के बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने की बात कही, ताकि विकास का लाभ सभी तक पहुंच सके। इस अवसर पर शी जिनपिंग ने घोषणा की कि चीन एपेक के व्यावहारिक सहयोग के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। इसके अलावा शेनझेन में एशिया-प्रशांत समुदाय अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। चीन डिजिटल तकनीक, सीमा पार डेटा प्रवाह, स्वच्छ ऊर्जा और लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए सहयोग संस्थान भी स्थापित करेगा। स्वागत भोज में अपने संबोधन के दौरान जिनपिंग ने शेनझेन के विकास का उल्लेख करते हुए इसे चीन की सुधार और खुलेपन की नीति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 1978 में एक छोटे मछुआरों के गांव के रूप में पहचाना जाने वाला शेनझेन आज आधुनिक अंतरराष्ट्रीय महानगर बन चुका है। इस शहर ने खुलेपन, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के दम पर उल्लेखनीय विकास किया है। उन्होंने कहा कि एपेक ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने और एशिया-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है। चीन की अध्यक्षता के दौरान एक साल में 16 शहरों में 300 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

पुतिन, जिनपिंग और ट्रंप की त्रिपक्षीय बैठक खत्म, डेढ़ घंटे तक चर्चा, दुनिया भर की निगाहें

बीजिंग/मॉस्को। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के बीच गुरुवार को हुई पहली त्रिपक्षीय बैठक समाप्त हो गई। चीन के शेनझेन स्थित 'किलिन शानझुआंग स्टेट रेजिडेंस' में आयोजित यह बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यवस्था, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

रूस की अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती ने आज बताया कि बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि द्वितीय विश्वयुद्ध में चीन, रूस और अमेरिका मुख्य विजेता रहे थे। ऐसे में तीनों देशों की जिम्मेदारी है कि वे युद्ध के बाद स्थापित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मजबूती से रक्षा करें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करने तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में मिली जीत के परिणामों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया। शी ने कहा कि चीन, रूस और अमेरिका को एक-दूसरे की ताकत का लाभ उठाते हुए व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना चाहिए। इसके साथ ही तीनों देशों को ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने वैश्विक ऊर्जा बाजार की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के दौरान पूर्व विश्व नेताओं की कार्यशैली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले के नेता अक्सर उन देशों से बातचीत करने से बचते थे, जिनके साथ उनके मतभेद होते थे। ट्रंप ने कहा, 'अक्सर ऐसा होता था कि पुराने नेता उन देशों से बात करने से बचते थे, जिनके साथ उनके मतभेद थे लेकिन हमारा नजरिया इसके बिल्कुल उलट है। उनके इस बयान को अंतरराष्ट्रीय मतभेदों के बावजूद संवाद बनाए रखने की हिमायत के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार जताया। उन्होंने आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा, 'आयोजन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! सबकुछ बहुत बढ़िया है।'

बांग्लादेश में श्रमिक नेताओं की गिरफ्तारी पर एमनेस्टी चिंतित, कार्रवाई रोकने की मांग

ढाका। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले कपड़ा श्रमिकों और ट्रेड यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी तथा उत्पीड़न रोकने की अपील की है। संगठन ने देश में श्रमिकों की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग और शांतिपूर्ण सभा तथा संगठन बनाने के अधिकारों का इस्तेमाल करने के कारण श्रमिकों को निशाना बनाया जा रहा है। एमनेस्टी की यह प्रतिक्रिया दो श्रमिक संगठनों के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आई है। पुलिस ने ग्रीन बांग्ला गारमेंट्स वर्कर्स फेडरेशन (जीबीजीडब्ल्यूएफ) की केंद्रीय अध्यक्ष मोस्सामत सुल्ताना बेगम और महासचिव इलियास को गिरफ्तार किया। दोनों पर चार नवंबर को ढाका के सावर इलाके में पुलिस वाहन में आग लगाने का आरोप है।

सावर थाने के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद सैफुल आलम ने बांग्लादेशी समाचार पत्र 'डेली वादा' को बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों हिंसा भड़का रहे थे और उनके संगठन के सदस्य पुलिस वाहन जलाने की घटना में शामिल थे। एमनेस्टी ने गिरफ्तारियों की निंदा करते हुए कहा कि विरोध-प्रदर्शन शुरू होने के बाद गिरफ्तार किए गए ये पहले ट्रेड यूनियन नेता नहीं हैं। संगठन के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में भी कई श्रमिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। इनमें बांग्लादेशी गारमेंट्स ट्रेड यूनियन फेडरेशन के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष मुस्तफा कमाल, रोजिना अख्तर सुमी, मोहम्मद अली अजगर, मोहम्मद मोर्शेद आलम कौसर और मोहम्मद फुआदुर रहमान निरजोन शामिल हैं। इस बीच, अमेरिका स्थित फेयर लेबर एसोसिएशन (एफएलए) और अमेरिकन अपैरल एंड फुटवियर एसोसिएशन (एएएफए) ने सुल्ताना बेगम और इलियास की तत्काल रिहाई की मांग की है। दोनों संगठनों ने उनकी गिरफ्तारी को 'अस्वीकार्य' बताया। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से उचित न्यूनतम वेतन तय करने के लिए शीघ्र और शांतिपूर्ण बातचीत सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साथ ही चेतावनी दी कि श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी और हिरासत से बातचीत की प्रक्रिया बाधित हुई है और जिम्मेदार आपूर्ति भागीदार के रूप में बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंचा है।

रूस, चीन और अमेरिका की साझा घोषणा: पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ेगी, परमाणु जोखिम कम करने पर बातचीत

शेनझेन (चीन)। रूस, चीन और अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन एवं आपूर्ति बढ़ाने और परमाणु जोखिम कम करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) की पहली त्रिपक्षीय बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणापत्र में यह बात कही गई है।

गुरुवार को जारी इस घोषणापत्र के अनुसार, तीनों देश सभी देशों के लाभ के लिए रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर सहमति बनी। तीनों नेताओं ने स्थिर ऊर्जा आपूर्ति के महत्व को दोहराया। उन्होंने माना कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला का सुचारु बने रहना जरूरी है। पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने की योजना को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। घोषणापत्र में तीनों देशों ने परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर बातचीत जारी रखने को लेकर सहमति जताते हुए कहा कि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं हो सकता और ऐसा युद्ध कभी नहीं होना चाहिए। इस बयान के जरिए तीनों देशों ने परमाणु संघर्ष रोकने और वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। संयुक्त घोषणापत्र में सरकारी



अधिकारियों को प्राप्त कानूनी छूट के सम्मान को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। दस्तावेज के अनुसार, तीनों नेताओं ने राज्यों की सहमति के सिद्धांत और सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली छूट का सम्मान करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) और इसी तरह की अन्य संस्थाओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रूस, चीन और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें सुधार करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। घोषणापत्र के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते तीनों देश चाहते हैं कि विश्व संस्था वैश्विक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सके और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के अपने मूल उद्देश्य को बेहतर तरीके से पूरा करे। शेनझेन में हुई इस त्रिपक्षीय बैठक और संयुक्त घोषणापत्र को वैश्विक कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु जोखिमों में कमी, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका और संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे मुद्दों पर तीनों महाशक्तियों की सहमति से अंतरराष्ट्रीय सहयोग की नई संभावनाएं सामने आई हैं।

पीओके सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में क्षेत्रीय और शरणार्थी कोटे को खत्म करने के फैसले को रद्द किया

मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सरकारी नौकरियों में क्षेत्रीय और शरणार्थी कोटे को पूरी तरह से खत्म करने के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि भौगोलिक आधार पर प्राथमिकता देना अपने आप में असंवैधानिक नहीं है लेकिन इसके लिए कानून का समर्थन और कम प्रतिनिधित्व के सबूत होने चाहिए। डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश राजा सईद अकरम और न्यायमूर्ति खालिद यूसुफ चौधरी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनाए फैसले में लोक सेवा आयोग (पीएससी) को निर्देश दिया कि वे उन सभी लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करें और पूरा करें, जिन्हें उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) के 16 अगस्त, 2025 के फैसले के बाद रोक दिया गया था।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने दशकों पुराने कोटे के प्रतिशत को बहाल नहीं किया। इसके बजाय, सरकार को निर्देश दिया कि वह मौजूदा क्षेत्रीय और शरणार्थी कोटे की व्यापक समीक्षा करे और उन्हें संवैधानिक व कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए। कोर्ट ने भर्ती के लिए एक अंतरिम भौगोलिक ढांचा तय किया है। इसके तहत, ग्रेड 1 से 7 तक के पदों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा के जरिए भरा जाएगा, जबकि ग्रेड 8 से 15 तक के पदों को जिला स्तर पर भरा जाएगा। डिवीजनल कार्यालयों में ग्रेड 1 से 15 तक के पदों को



संबंधित डिवीजन के उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा से भरा जाएगा। वहीं, राज्यस्तरीय संस्थानों में (ग्रेड चाहे जो भी हो) और ग्रेड 16 व उससे ऊपर के सभी पदों को राज्य के नागरिकों के बीच खुली मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में चयन पूरी तरह से निर्धारित योग्यताओं, उपयुक्तता और मेरिट पर निर्भर करेगा।

अगर संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है तो नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया का दायरा बढ़ाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश अकरम ने फैसले में टिप्पणी की है कि उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय, क्षेत्र-आधारित या शरणार्थी-संबंधी भर्ती व्यवस्थाओं को पूरी तरह से असंवैधानिक मानकर गलती की थी। इसमें कहा गया है कि पीओके सिविल सर्वेंट्स एक्ट, 1976 और सिविल सर्वेंट्स रूल्स, 1977 के तहत बना कानूनी ढांचा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों और पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार के अधिकार को मान्यता देता है। हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार असीमित नहीं है और ऐतिहासिक कोटा व्यवस्था को किसी तार्किक और ठोस आधार के बिना हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता। खंडपीठ ने पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों के लिए आरक्षित कोटे पर भी अलग से विचार किया। इसमें कहा गया कि 'स्टेट सब्जेक्ट' (राज्य के नागरिक) के रूप में उनकी स्थिति, किसी विशेष कोटा या प्राथमिकता के जारी रहने पर निर्भर नहीं करती है।

भविष्य को लेकर आशावादी युवाओं की सूची में नेपाल दुनिया में तीसरे स्थान पर, आर्थिक उम्मीदों में अव्वल

काठमांडू। भविष्य को लेकर सबसे अधिक आशावादी युवाओं वाले देशों की सूची में नेपाल ने दुनिया में तीसरा स्थान हासिल किया है। ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड स्कोलास्टिका एकेडमी द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में नेपाली युवाओं ने व्यक्तिगत भविष्य के प्रति आशावाद के मामले में 5 में से 4.24 अंक हासिल किए हैं। इस सर्वेक्षण में शामिल 41 देशों में नेपाल तीसरे स्थान पर रहा। इस सूची में श्रीलंका 4.32 अंकों के साथ पहले और केन्या 4.31 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। सर्वेक्षण के अनुसार, व्यक्तिगत भविष्य के प्रति आशावाद के मामले में नेपाल को 5 में से 5 अंक मिले हैं। वहीं, आर्थिक भविष्य के प्रति आशावाद में नेपाल ने 4.80 अंक हासिल किए हैं, जो सर्वेक्षण में शामिल सभी देशों में सबसे अधिक है।

यह परिणाम दर्शाता है कि नेपाल की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद यहां के युवाओं को अपने व्यक्तिगत भविष्य और आर्थिक संभावनाओं पर काफी भरोसा है। सर्वेक्षण में नेपाली युवाओं ने समाज के भविष्य के प्रति आशावाद में 4.00, राजनीतिक भविष्य के प्रति 3.80 और पर्यावरणीय भविष्य के प्रति 3.60 अंक हासिल किए हैं। समग्र रूप से सबसे अधिक आशावादी युवाओं वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में कजाकिस्तान 4.17 अंकों के साथ चौथे, साइप्रस 4.09 अंकों के साथ पांचवें, कनाडा 4.08 अंकों के साथ छठे और नाइजीरिया भी 4.08 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है। इंडोनेशिया और रूस ने समान रूप से 4.07 अंक हासिल किए हैं, जबकि आर्मेनिया 4.06 अंकों के साथ दसवें स्थान पर है। इसके विपरीत, कुवैत 2.92 अंकों के साथ सबसे कम आशावादी युवाओं वाला देश बना है। रवांडा 3.20, तुर्की और फ्रांस 3.22 तथा पोलैंड 3.24 अंकों के साथ सूची में सबसे निचले पायदान पर हैं।

ब्रिटेन 3.61 अंकों के साथ 41 देशों में 33वें स्थान पर है। ब्रिटिश युवाओं ने राजनीतिक भविष्य के प्रति आशावाद में केवल 3.04 और पर्यावरणीय भविष्य के प्रति 3.06 अंक हासिल किए हैं। ऑक्सफोर्ड स्कोलास्टिका एकेडमी के अनुसार, इस सर्वेक्षण में 100 देशों के युवाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया था। हालांकि, पर्याप्त प्रतिक्रियाएं मिलने वाले 41 देशों के विद्यार्थियों के आंकड़ों का ही विश्लेषण किया गया। अध्ययन में कुल 1,433 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। सर्वेक्षण के मुताबिक, दुनिया भर के युवा अपने व्यक्तिगत भविष्य को लेकर सबसे अधिक आशावादी हैं। वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत भविष्य के प्रति आशावाद का औसत स्कोर 4.40 रहा है। इसके विपरीत, राजनीतिक भविष्य के प्रति आशावाद सबसे कम 3.29 अंक दर्ज किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष सार्वजनिक करते हुए ऑक्सफोर्ड स्कोलास्टिका एकेडमी की सह-निदेशक लाविनिया एबेल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), युद्ध, जीवनयापन की बढ़ती लागत और रोजगार से जुड़ी चुनौतियां युवाओं में चिंता और निराशा बढ़ा सकती हैं।

एक नजर

झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर स्पीकर ने की उच्चस्तरीय बैठक

रांची,एजेंसी। झारखंड विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस आगामी 22 नवंबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर होनेवाले समारोह को लेकर स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक की। स्पीकर कक्ष में आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावे राज्य सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में 22 नवंबर को सुबह 11:30 बजे झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित होनेवाले स्थापना दिवस समारोह के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की ओर से कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम के मुख्य तिथि होंगे। इस अवसर पर विधायी उत्कृष्टता चयन समिति द्वारा चयनित सदस्य को बिरसा मुण्डा उत्कृष्ट विधायक सम्मान, उत्कृष्ट विधान सभा कर्मियों को स्व0 कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मौके पर पूर्व सदस्यों का सम्मान, खिलाड़ियों का सम्मान, एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान त्रैमासिक पत्रिका 'उड़ान' (104वां अंक) एवं अन्य पुस्तक का विमोचन-लोकार्पण भी होगा। स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में स्थापना दिवस को लेकर निर्देश दिए गए। स्थापना दिवस समारोह में, आवासन, सुरक्षा तथा यातायात से संबंधित निर्देश स्पीकर के द्वारा विभागीय पदाधिकारियों को दिए गए। साथ ही आगामी 25 एवं 26 नवंबर को आहूत विशेष सत्र के सुचारू संचालन के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा विधानसभा के प्रभारी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पुलिस निरीक्षक मुख्यालय, उपायुक्त, वरीय आरक्षी अधीक्षक, नगर आयुक्त तथा संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

देश के 600 जिलों में बागेश्वर सेवा मंडल का होगा गठन : पं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा के बेंती स्थित देवरहवा बाबा मंडपम में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की ओर से आयोजित श्रीराम कथा के तीसरे दिन गुरुवार को धर्म, सनातन और राष्ट्रवाद का संदेश प्रमुखता से गूंजा। गुरुवार को कथा का तीसरा दिन था और विश्राम हुआ, वहीं शुक्रवार को बागेश्वर सरकार द्वारा दरबार लगाया जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के करीब 600 जिलों में बागेश्वर सेवा मंडल गठित करने का संकल्प जताते हुए अगले छह वर्षों में प्रत्येक जिले में 11 हजार बागेश्वर सेवादार तैयार करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्रभक्त तैयार किए जाएंगे, जो सनातन संस्कृति, गौमाता, गंगा, गीता और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के लिए समर्पित रहेंगे।

कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दुनिया में एक ऐसा देश होना चाहिए, जहां दुनिया भर में सताए गए हिंदुओं को सम्मान और सुरक्षित स्थान मिल सके। भारत की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपरा को मजबूत करना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनका अभियान केवल कथा सुनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से समाज में धार्मिक चेतना, एकता और राष्ट्रभक्ति का भाव जगाना भी उद्देश्य है। उन्होंने बागेश्वर सेवा मंडल की परिकल्पना को विस्तार से समझाते हुए कहा कि छह साल के भीतर देश के सभी जिलों तक इस अभियान को पहुंचाने का प्रयास है। प्रत्येक जिले में 11 हजार बागेश्वर सेवादार तैयार करने का लक्ष्य है। इन सेवादारों के घरों में गाय हो, दरवाजे पर राष्ट्रध्वज या भगवा ध्वज लहराए, आसपास के मंदिर स्वच्छ रहें और उनमें नियमित पूजा-पाठ हो। इसके साथ ही हर महीने बैठक कर सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा की जाए। हनुमान जी और सोने की लंका का प्रसंग सुनाकर उन्होंने समाज को सकारात्मक सोच का संदेश भी दिया। कहा कि सोना भी गलत जगह और गलत उद्देश्य से जुड़ जाए तो उसका विनाश हो सकता है। रावण ने जब हनुमान जी को लंका में बंदी बनाया तो उनकी शक्ति परखने के लिए पूंछ में आग लगवाई गई, लेकिन हनुमान जी सुरक्षित रहे और सोने की लंका जलकर राख हो गई। इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि केवल बाहरी वैभव ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के विचार, आचरण और कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरे दिन की कथा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। बेंती पहुंचने पर जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने उनका स्वागत किया।

एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औद्योगिक केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर निवेश के प्रमुख आधार

सद्भावना टुडे, वरिष्ठ संवाददाता

नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) के 23वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को निवेश, विनिर्माण और औद्योगिक विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आईएएस अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि राज्य सरकार एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े औद्योगिक नोड्स की संख्या 27 से बढ़ाकर 45 करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहा एक्सप्रेसवे नेटवर्क आर्थिक बदलाव और औद्योगिक विस्तार का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। उन्होंने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का उल्लेख करते हुए कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से उद्योगों को बाजारों, लॉजिस्टिक्स हब और विनिर्माण केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा मिल रही है।



नोएडा और जेवर एयरपोर्ट निवेश के प्रमुख आकर्षण

श्री भाटिया के अनुसार, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लगभग 55 से 60 प्रतिशत हिस्सा नोएडा और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में केंद्रित है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नए निवेश और जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से इस क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि एनसीआर के बाहर भी औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, बलरामपुर और फिरोजाबाद सहित विभिन्न जिलों में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकास के उन्नत चरण में हैं। सरकार का लक्ष्य इस नेटवर्क को 45 औद्योगिक नोड्स तक विस्तारित करना है। उन्होंने कहा कि अब चुनौती निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ बड़े निवेशकों की बढ़ती मांग के अनुरूप पर्याप्त औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराना भी है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश सरकार के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के विशेष सचिव राज कमल यादव ने राज्य की कृषि उत्पादकता, कच्चे माल की उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अनुकूल बताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बागवानी उत्पादकता लगभग 20.03 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पिछले 18 महीनों के दौरान 628 परियोजनाओं को मंजूरी, लगभग 5,200 करोड़ रुपये का निवेश और करीब 800 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन स्वीकृत किए गए हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार 5 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं पर 35 प्रतिशत तक पूंजी सब्सिडी, कोल्ड चेन परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये तक प्रोत्साहन तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है।

विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां

कोचर एंड कंपनी की पार्टनर कंचन सिन्हा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की एफडीआई और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 नीति वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार, भूमि प्रोत्साहन सहित लचीली निवेश व्यवस्था के तहत लगभग 26,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

बुंदेलखंड में औद्योगिक स्मार्ट सिटी का विकास

बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) के सीईओ एवं आईएएस अधिकारी संजय कुमार खत्री ने बताया कि बुंदेलखंड में लगभग 62,000 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित करने की योजना है। इसमें प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचा, आधुनिक सुविधाएं और बड़े निवेशकों के लिए भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। इस परियोजना के माध्यम से विनिर्माण, डेटा सेंटर, रक्षा, एयरोस्पेस और उन्नत उद्योगों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

रक्षा उत्पादन और एमएसएमई को भी बढ़ावा

यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मुख्य महाप्रबंधक सेवानिवृत्त कर्नल संजय सिंह ने बताया कि कॉरिडोर में पांच वर्षों के भीतर 67 औद्योगिक आवंटन किए गए हैं, 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को सुविधाजनक बनाया गया है और 13 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के निदेशक अंकित कुमार अग्रवाल ने तकनीक, कौशल विकास और पूंजी तक पहुंच को एमएसएमई विकास के प्रमुख आधार बताया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सेंटर, कौशल विकास कार्यक्रम और विभिन्न फंडिंग योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई जा रही है।

भारत-अमेरिका आर्थिक सहयोग के नए अवसर

सम्मेलन में हुई चर्चाओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश तेजी से विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रौद्योगिकी और एयरोस्पेस के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे, व्यापक एक्सप्रेसवे नेटवर्क, निवेशक-अनुकूल नीतियों और औद्योगिक कॉरिडोर के विस्तार के जरिए राज्य घरेलू तथा वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और भारत-अमेरिका आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयासरत है।

जंगलों में मोबाइल टावर लगाने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोपरि : हेमंत सोरेन

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, जैव विविधता के संरक्षण तथा वन क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ वन क्षेत्रों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों एवं सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क और संचार सुविधाओं की आवश्यकता पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि दूरदराज के गांवों और जंगलों में रहने वाले लोगों को बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। हालांकि, वन क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित करने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मोबाइल टावरों से निकलने वाले संभावित रेडिएशन के प्रभाव तथा अन्य पर्यावरणीय पहलुओं का समुचित आकलन किया जाए, ताकि वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतिक आवासों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे। इस दिशा में आवश्यक तकनीकी एवं पर्यावरणीय सावधानियां सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों एवं संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के साथ वहां निवास करने वाले लोगों की आजीविका, जीवनयापन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े पहलुओं को भी प्राथमिकता दी जाए। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ स्थानीय लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए। संरक्षण और स्थानीय जनजीवन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने पौधरोपण एवं वन क्षेत्र के विकास को लेकर कहा कि राज्य में ऐसे पेड़-पौधे लगाए जाने चाहिए, जो उपयोगी हों और जिनका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। साथ ही, पौधों का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उनके फल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन वन्यजीवों के लिए भी उपयोगी हों। उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ मानव जीवन और वन्यजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक हों।

एवरेस्ट फतेह करने के लिए आखों में रोशनी जरूरी नहीं: छोनजिन आंगमो



धर्मशाला। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली और एकमात्र नेत्रहीन महिला छोनजिन आंगमो ने कहा है कि विकलांगता के प्रति समाज की सोच बदलने के लिए उन्होंने पर्वतारोहण को चुना। उन्होंने कहा कि एवरेस्ट फतेह करने के लिए आंखों की रोशनी जरूरी नही है। कुछ करने का जज्बा और लगन किसी भी बाधा को पार कर सकती है। वह यूरोप और अफ्रीका की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी हैं। किन्नौर की रहने वाली आंगमो दिल्ली में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में अधिकारी हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह में राष्ट्रीय पुरास्कर से सम्मानित किया था। वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइकलिंग, तैराकी, मैराथन, मार्शल आर्ट एवं अन्य खेलों में भी पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।

छोनजिन आंगमो टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट के वार्षिक 'धन्यवाद दिवस' समारोह में मुख्य अतिथि थीं। ट्रस्ट के संस्थापक निदेशक जामयांग ने उन्हें हिमाचली शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अर्चना फुल्ल ने की। कार्यक्रम में टोंगलेन स्कूल के में पढ़ने वाले, झुग्गी बस्तियों के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छोनजिन आंगमो ने कहा कि अब उनका सपना दुनिया के चार अन्य सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों पर कदम रखकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाना है। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची सातों पर्वत चोटियों पर कोई भी दृष्टिबाधित महिला चढ़ाई नहीं कर सकी है। उन्होंने झुग्गी बस्तियों के बच्चों से कहा की सपने देखो और उनमें रंग भरने के लिए पूरी ताकत लगा दो। अगर हिम्मत कर लो तो कोई भी लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।

टोंगलेन ट्रस्ट द्वारा समाज के सबसे कमजोर वर्गों के हित में किए जा रहे हैं कार्यों के लिए भिक्षु जामयांग को बधाई दी और प्रेरणा का स्रोत बताया। उमंग फाउंडेशन शिमला के अध्यक्ष प्रो अजय श्रीवास्तव ने कहा कि छोनजिन आंगमो को मुख्य अतिथि बना कर संस्था ने वास्तव में वंचित वर्ग के बच्चों को बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। भिक्षु जामयांग ने पिछले 22 वर्षों के दौरान संस्था के संघर्ष और उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उनको सम्मानित भी किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 'टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2027' में वैश्विक स्तर पर 69वां स्थान हासिल किया

एम.जबिउल्लाह

नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने 'टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2027' में वैश्विक स्तर पर 69वां स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि वैश्विक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की बढ़ती प्रतिष्ठा और मजबूत उपस्थिति को फिर से रेखांकित करती है। प्रतिष्ठित 'THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2027' के नवीनतम संस्करण में JMI को दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। यह रैंकिंग शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान सृजन, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सम्बद्धता में विश्वविद्यालय के निरंतर योगदान को दर्शाती है। यह रैंकिंग विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन 'इंटरडिसिप्लिनरी' अनुसंधान से जुड़े प्रमुख पैमानों—जैसे इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट—के आधार पर करती है। इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि विश्वविद्यालय किस तरह सहयोगात्मक और अंतर-विषयक वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से जटिल वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में योगदान दे रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर 69वां स्थान हासिल करना, विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अनुसंधान इको सिस्टम को मजबूत करने में योगदान दिया है। यह उपलब्धि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रभावशाली अनुसंधान, नवाचार और संस्थागत विकास के प्रति विश्वविद्यालय की निरंतर प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।



JMI के कुलपति, प्रो. मज़हर आसिफ़ ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं, छात्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में JMI के प्रदर्शन में उनके सामूहिक योगदान की सराहना की और शैक्षणिक उत्कृष्टता, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, नवाचार, अंतर-विषयक सहयोग तथा वैश्विक शैक्षणिक सम्बद्धता को आगे बढ़ाने के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दोहराया। छुस्ड्ढ के रजिस्ट्रार, प्रो. मो. महताब आलम रिज़वी ने भी उच्च रैंकिंग हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विज्ञान और अंतर-विषयक विज्ञान के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई प्रगति और अत्याधुनिक अनुसंधान को दर्शाती है। यह JMI के संकाय सदस्यों द्वारा शिक्षण और अनुसंधान के उच्च मानक को बनाए रखने और उसमें साल-दर-साल निरंतर सुधार करने की मान्यता है; इन संकाय सदस्यों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान हासिल की है। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (IQAC) की मानद निदेशक, प्रो. रफत परवीन ने पूरे छुस्ड्ढ समुदाय को बधाई दी। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक संस्थागत डेटा और जानकारी को संकलित करने, सत्यापित करने और उसे जमा करने की प्रक्रिया में IQAC टीम के समर्पित प्रयासों की सराहना की। विश्वविद्यालय, IQAC टीम के साथ-साथ विभिन्न संकायों, विभागों, केंद्रों और प्रशासनिक इकाइयों के कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान को भी स्वीकार करता है। इन सभी के समन्वित प्रयासों ने छुस्ड्ढ की संस्थागत प्रोफ़ाइल को मजबूत करने और वैश्विक रैंकिंग फ्रेमवर्क में इसकी भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपने शैक्षणिक, अनुसंधान और गुणवत्ता आश्वासन इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत करने, तथा अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा भाषणी और एनआईईएलआईटी का सहयोग

नई दिल्ली। देश में डिजिटल शिक्षा और तकनीकी ज्ञान को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) के बीच बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया है। यह सहयोग ' भाषणी फॉर सेवा के तहत किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य देश के अलग-अलग भाषाई क्षेत्रों के विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों तक उनकी पसंदीदा भारतीय भाषाओं में डिजिटल ज्ञान, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े अवसर पहुंचाना है।

इस समझौते का आदान-प्रदान भाषणी की इकोसिस्टम एंगेजमेंट प्रमुख स्वाति बिष्ट चौधरी और एनआईईएलआईटी के रजिस्ट्रार डॉ. एस. के. धुरंधर ने दोनों संस्थानों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया।



इस साझेदारी के तहत भाषणी की एआई आधारित भाषा तकनीकों के शैक्षणिक, प्रशिक्षण और संस्थागत प्लेटफॉर्म से जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

इसके माध्यम से तकनीकी पाठ्यक्रमों, अध्ययन सामग्री, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण संसाधनों को कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर काम होगा। समझौते में एआई आधारित अनुवाद, स्पीच टेक्नोलॉजी और अन्य भाषा संबंधी तकनीकी समाधानों के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इसके अलावा विभिन्न तकनीकी विषयों के लिए विशेष भाषा संसाधन तैयार करने, रिसर्च, नवाचार और भाषाई डेटा के योगदान को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जाएगा। इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की जानकारी तकनीकी शिक्षा हासिल करने में बाधा न बने।

देश के अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि के विद्यार्थी अपनी मातृभाषा या पसंदीदा भारतीय भाषा में तकनीकी विषयों को समझ सकें और नए तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। भाषणी और एनआईईएलआईटी की साझेदारी के जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए बहुभाषी डिजिटल लर्निंग का वातावरण तैयार करने पर भी काम होगा।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)